● वर्ष-3

● अंक-294

रायपुर, शनिवार 20 जुलाई 2024

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› पहाड़ों चादर ओढ़े मेघालय

किसानों के हित में साय सरकार का फैसला

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में होगा संशोधन

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 जुलाई को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन होने से अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन अथवा अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार द्वारा संचालित ई-नाम पोर्टल (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी-बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे, इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा।

संशोधन प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर अब ''मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क'' शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित है। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा। इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश और परिपत्रों को निरस्त कर दिया है। जिसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितम्बर 2019 को जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमिस्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में 24 फरवरी 2024 को जारी परिपत्र शामिल हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आबंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाईट में प्रदर्शित की जाएगी और इस विषय में कोई भी आपत्ति और शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जीएसटी कॉउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यय लिये जाने के प्रावधान को युक्तियुक्त बनाने एवं पान मसाला, गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के परिपेक्ष्य में केन्द्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024, 15 फरवरी 2024 अधिसूचित है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी तद्नुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए) विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।

कांवड़ यात्रा विवाद से एनडीए में घमासान

अमित शर्मा

कावड़ यात्रा पर शुरू हुआ घमासान और गंभीर होता जा रहा है। एनडीए के सहयोगी दलों जदयू और आरएलडी के बाद चिराग पासवान ने भी इस आदेश के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। एनडीए के सहयोगी दलों ने उत्तर प्रदेश सरकार के उसे आदेश का विरोध किया है जिसमें कावड़ यात्रा के मार्ग में सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों के सामने दुकान के मालिक का नाम लिखने का आदेश दिया है। विपक्षी दलों ने भी इस आदेश पर योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि इस आदेश के पीछे भी एक सोची समझी राजनीति हो सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उसका आरोप है कि मतदाताओं के सांप्रदायिक आधार पर विभाजन को बढ़ाने के लिए ही इस तरह का आदेश जारी किया गया है।

सबसे पहले मुजफ्फरनगर की पुलिस ने यह आदेश दिया था कि कावड़ यात्रा के मार्ग में दुकान लगाने वाले रेहडी-पटरी और ढाबे वाले दुकानदार अपनी दुकानों के सामने अपने नाम की प्लेट लगाएं। इसके बाद इस आदेश को पूरे उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा मार्गों पर लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया। मामला केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी पूरे राज्य में कावड़ यात्रा मार्गों पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों के लिए मालिकों के नाम और रेट की लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया।

सहयोगी दलों का विरोध

भाजपा सरकारों के इस आदेश पर तुरंत ही एनडीए में घमासान मच गया। सबसे पहले एनडीए के जनता दल यूनाइटेड ने इस आदेश को गलत बताया। पार्टी के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में यूपी से बड़ी कांवड़ यात्रा निकलती है लेकिन कहीं भी इस तरह का आदेश नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि इससे समाज में भेदभाव बढ़ेगा। इस आदेश की समीक्षा की जानी चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के एनडीए के दूसरे सहयोगी दल आरएलडी ने भी इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया। अब मोदी के %हनुमान% कहे जाने वाले चिराग पासवान ने भी इस आदेश को गलत बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है।

उपचुनाव महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद उपचुनावों में भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वह इन 10 सीटों में ज्यादा से ज्यादा पर जीत हासिल कर अपनी बढ़त बनाना चाहती है। इससे उसका मनोबल बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह का वर्तमान माहौल है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए चुनौतियां बढ़ी हुई हैं।

एक सॉफ्टवेयर अपडेट से मच गई दुनिया में अफरा-तफरी

नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आउटेज ने दुनिया के समक्ष कई चिंताजनक सवाल खड़े कर दिए हैं। इस आउटेज के कारण दुनियाभर के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा आउटेज होने से विभिन्न देशों में कई एयरलाइन्स भी ठप हो गईं। वैश्विक आईटी आउटेज के कारण, देश भर में उड़ान संचालन बाधित हो गया, जिससे कोलकाता हवाई अड्डे पर यात्रा और उड़ान कार्यक्रम प्रभावित हुए। हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार, 14 प्रस्थान और 11 आगमन सहित कम से कम 25 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कोलकाता से इंडिगो की दो उड़ानें - एक सिलचर के लिए और दूसरी बेंगलुरु के लिए रद्द कर दी गईं। हवाई अड्डे से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 40 से अधिक प्रस्थान और 29 आगमन उड़ानों में देरी हुई है। हवाईअड्डे के अधिकारियों ने कहा कि हवाईअड्डे पर समस्या शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू हुई, पहली प्रभावित उड़ान सुबह 10.30 बजे इंडिगो एयरलाइंस की थी। कोलकाता एयरपोर्ट ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि यात्रियों को अपडेट के लिए अपनी संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। हम ध्द्वष्ह्लश्ह्यश्द्घह्ल ऽ5ह्लह्द के साथ एक नेटवर्क-व्यापी समस्या का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण हवाई अड्डों पर देरी हो रही है। चेक-इन धीमा हो सकता है और कतारें लंबी हो सकती हैं। हमारी डिजिटल टीम इसे तेजी से हल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रही है। पोस्ट में कहा गया कि सहायता के लिए, कृपया हमारी ऑन-ग्राउंड टीम से संपर्क करें। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। एयरपोर्ट पर पूरी तरह से अफरा-तफरी का माहौल है। हवाईअड्डे के एक कर्मचारी ने कहा कि शुरुआत में यात्रियों को अच्छी तरह से सूचित नहीं किया गया था, पूछताछ और आगमन प्रस्थान द्वार पर भी लंबी कतारें थीं।

युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सरकार की खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आईडेंटीफिकेशन- कीर्ति पहल के दूसरे चरण का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। खेल मंत्रालय ने कहा है कि कीर्ति की परिकल्पना आधुनिक आई सी टी उपकरणों और वैश्विक सर्वोत्तम तरीकों के आधार पर प्रतिभाओं को पहचानने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य एक ही मंच पर जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान करने की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।।

प्रमुख समाचार

हमारी अलग सोच, भारत का अमेरिका को जवाब

नई दिल्ली। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया था। इसके बाद से अमेरिका लगातार भारत को लेकर बयानबाजी कर रहा है। इस बीच, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा था कि संघर्ष के समय रणनीतिक स्वायत्तता मायने नहीं रखती। अब भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत भी उन देशों में शामिल है, जो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का मान रखते हैं। जाहिर है कि अमेरिका के राजदूत को अपनी बातें रखने का अधिकार है। इस मामले में भारत की भी अपनी अलग सोच है। अमेरिका के साथ हमारी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के तहत, एक-दूसरे के नजरियों का सम्मान करने साथ, हम एक दूसरे के मुद्दों पर सहमति और असहमति जता सकते हैं।' भारत अमेरिका के संबंधों पर रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक, वैश्विक साझेदारी है। दोनों देशों के पास चर्चा करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। दोनों पक्षों के बीच कई विषयों पर एक-दूसरे के साथ बातचीत होती रही है। जो भी एक-दूसरे के हित में है, उस मुद्दे पर चर्चा की जाती है।

क्षेत्रीय दलों में बीआरएस ने की सबसे अधिक कमाई

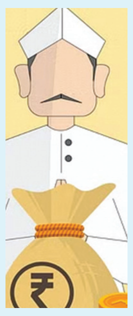

नई दिल्ली। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और सबसे अधिक खर्च करने वाली पार्टियों का ब्योरा जारी किया है। एडीआर के अनुसार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी ने इस दौरान सबसे अधिक 737.67 करोड़ रुपये कमाए। इसके अलावा एडीआर ने सबसे अधिक खर्च करने वाली शीर्ष पांच पार्टियों की भी सूची जारी की है। एडीआर के मुताबिक इस सूची में सबसे पहला स्थान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का है। एडीआर का कहना है कि टीएमसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक 181.18 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके बाद युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी)79.32 करोड़, बीआरएस ने 57.47 करोड़, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने 52.62 करोड़ और समाजवादी पार्टी (एसपी) ने 31.41 करोड़ रुपये खर्च किए। एडीआर की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 देश की 57 में से 39 क्षेत्रीय पार्टियों की कमाई और खर्च का ब्योरा जारी किया गया है।

सोनम किन्नर ने उप्र में राज्य मंत्री पद से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में स्थितियां सहज नहीं दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सोनम किन्नर ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, सरकार ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। सोनम किन्नर ने हाल ही में राज्यपाल से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके इस्तीफे की अटकलें लगने लगी थीं। सोनम किन्नर पहले समाजवादी पार्टी में थीं। सपा छोड़कर वह भाजपा में शामिल हुई थीं। सोनम किन्नर ने कहा है कि चूंकि लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, इसलिए वह इसे अपने ऊपर लेंगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वह अब सरकार के बजाय संगठन के भीतर काम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने सरकार के अधिकारियों पर पार्टी कार्यकर्ताओं की चिंताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि सोनम किन्नर हमेशा नौकरशाही कार्यप्रणाली के खिलाफ मुखर रही हैं .

स्वामी प्रसाद मौर्य और बेटी संघमित्रा भगोड़ा घोषित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को बेटी संघमित्रा मौर्य के साथ भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दीपक कुमार स्वर्णकार मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी, बदायूं से पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य और तीन अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के तहत आदेश जारी किया है। एसीजेएम तृतीय एमपी-एमएलए आलोक वर्मा की अदालत ने यह कदम तब उठाया जब मौर्य समेत अन्य आरोपी तीन समन, दो जमानती वारंट और एक गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस विवादास्पद मामले में पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य शामिल हैं। इससे पहले मौर्य परिवार ने इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, जस्टिस जसप्रीत सिंह की अदालत ने मौर्य को फटकार लगाते हुए कहा, %%आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, आपको एमपी-एमएलए कोर्ट में वापस आना होगा।

शनिवार को ऑनलाइन जारी होगा नीट परीक्षा का रिजल्ट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) कल, 12 जुलाई को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेडिकल परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी लोग अपने उपयोगकर्ता नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण का उपयोग करके अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार परिणाम जारी होने के बाद, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देख सकेंगे। एनटीए द्वारा पारित आदेश के अनुसार, ह्वश्वश्वञ्ज त्न 2024 के परिणाम 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे प्रकाशित किए जाएंगे। मेडिकल उम्मीदवार कल, 18 जुलाई को आधिकारिक वेबसाइट से शहर और केंद्र-वार एनईईटी यूजी परिणाम अलग से डाउनलोड कर सकेंगे। शीर्ष अदालत ने एजेंसी से कहा है कि वह उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को वेबसाइट पर प्रकाशित करे लेकिन छात्र की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पारित किया।

'संविधान हत्या दिवस' को कैसे देखें

अवधेश कुमार

25 जून यानी आपातकाल लगाने की तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की नरेंद्र मोदी सरकार की घोषणा पर आ रही प्रतिक्रियाओं में कुछ तो स्वाभाविक है किंतु कुछ आश्चर्य में भी डालने वाली हैं। कांग्रेस पार्टी का इसके विरुद्ध अलग-अलग प्रकार का तर्क समझ में आता है। लेकिन जिन नेताओं और पार्टियों ने आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष किया, जिनमें से कई की पहचान आपातकाल विरोधी संघर्ष से ही बनी वह भी खुलकर आपातकाल की आलोचना के लिए तैयार नहीं है।

ऐसा वातावरण बना है मानो आपातकाल के विरुद्ध केवल भाजपा हो और शेष पार्टियों ने उसे सही मान लिया हो। आपातकाल अगर सही है और उस दिवस को याद नहीं किया जाए तो आज अनेक नेता और पार्टियां, जो वहीं से उभर कर सत्ता में आए और आज भी हैं, उन सबकी पूरी राजनीति अवैध और अनैतिक हो जाएगी। चूंकि गृह मंत्रालय ने सरकारी गजट में इसे शामिल कर दिया है, इसलिए जब तक कोई सरकार इसको निरस्त नहीं करती यह अब सरकारी कार्यक्रमों का अंग बन चुका है।

स्वयं गृहमंत्री अमित शाह ने इसके बारे में एक्स पर पोस्ट डाला एवं एक पृष्ठ का वक्तव्य भी जारी किया। साफ है कि सरकार के अंदर कई दिनों से इस पर मंथन चल रहा था। ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह विचार किया गया हो और शाम को गजट जारी हो जाए। सामान्य तौर पर यह निष्कर्ष निकालना गलत नहीं है कि मोदी सरकार ने कांग्रेस एवं विपक्ष को जैसे को तैसे की भाषा में जवाब देने के लिए संविधान हत्या दिवस की घोषणा की है। जब कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्ष भाजपा संविधान खत्म कर देगी तथा संविधान बचाओ को राजनीति और चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाते हैं तो भाजपा के लिए इसका प्रभावी प्रत्युत्तर देना स्वाभाविक है। सब जानते हैं कि इस देश के वर्तमान ढांचे में संविधान को खत्म कर देना या उसका गला घोंट देना और पूरे राजनीतिक, प्रशासनिक ढांचे को आमूल रूप से बदल देना संभव नहीं है। यह झूठ चुनाव में मुद्दा बना तथा एक बड़े वर्ग तक पहुंचा। संविधान खत्म होने के साथ ही आरक्षण खत्म करने की भी बात थी और दोनों एक-दूसरे से सन्नद्ध थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति अटैक इज द बैस्ट डिफैंस यानी आक्रमण सबसे बड़ा बचाव की रही है। इस बार के चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा को रक्षात्मक या बचाव की मुद्रा में ज्यादातर समय रहना पड़ा। भाजपा मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को समझाने में सफल नहीं रही कि विपक्ष गलत मुद्दा बना रहा है। चुनाव परिणाम के बाद निश्चय ही इस पर विचार हुआ है। ध्यान रखिए कि 25 जून को सरकारी कार्यक्रम भले आज घोषित किया गया हो किंतु हर वर्ष देश भर में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो आपातकाल के काले अध्याय को याद करते हुए कार्यक्रम रखते हैं। अनेक पार्टियों के नेता उसमें शामिल होते रहे हैं और आज भी होते हैं। आज सपा इस मामले पर खामोश है या प्रश्न उठा रही है किंतु स्वयं मुलायम सिंह यादव आपातकाल विरोधी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री रहते हुए भी शामिल होते रहे। 5 जून को जयप्रकाश जी का संपूर्ण क्रांति दिवस भी अलग-अलग स्थानों में हर वर्ष मनाया जाता है।

निश्चित रूप से इस मामले में भाजपा की रणनीति यही है कि देश के आम लोग समझ लें कि संविधान को खत्म करने की कोशिश किसने की। इस देश में अगर किसी काल में संविधान व्यवहार में खत्म था तो वह आपातकाल का दौर ही था। यद्यपि 25 जून ,1975 को आपातकाल भी संविधान की धारा 352 के तहत ही लगा था। आपातकाल लगने के बाद व्यवहार में सारी शक्तियां एक व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी में निहित हो गई थीं। सरकारी टैलीविजन दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय संजय गांधी के निवास या फिर सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल के आवास एवं कार्यालय से ही उसका संचालन होता था। समाचार पत्र छापने से पहले सैंसरशिप अधिकारी को भेजा जाता था जो बताता था कि किस समाचार में क्या बदलना है, कितना छाप सकते हैं और तभी वह प्रैस में छपने जाता था।

वैसे जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद आंतरिक आपातकाल लगाने का प्रावधान संविधान से लगभग खत्म कर दिया। यह प्रचार भी झूठ है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक व्यक्ति के शासन की स्थिति संविधान में परिवर्तन कर ला सकती है। एक बार आपातकाल लगाने का परिणाम देश भुगत चुका है और स्वयं कांग्रेस पार्टी भी चुनाव में बुरी तरह पराजित हुई। इतने वर्षों बाद संविधान हत्या दिवस मनाने की प्रासंगिकता और उपयोगिता पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। निःसंदेह, आपातकाल के बाद सत्ता में आई जनता पार्टी की सरकार या उसके बाद जो भी गैर-कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई उसने ऐसा निर्णय नहीं किया। किसी ने नहीं किया इसलिए आगे वैसा नहीं किया जाए इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जब आप संविधान खत्म करने का आरोप लगाते हैं तो इस पर पूरी बहस होनी चाहिए और संविधान से छेड़छाड़ या संविधान के साथ के दुरुपयोग के जितने अवसर हैं वह सब देश के सामने आने ही चाहिएं। 50 वर्ष वह अवसर होता है जब हम उस घटना को लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचार करते हैं, उससे सीख लेते हैं, प्रेरणा देते हैं और उनसे जुड़े व्यक्तियों को उनकी भूमिका के अनुरूप याद करते हैं।

बीजापुर के मुदवेंडी में आईईडी ब्लास्ट, दो जवान घायल, अस्पताल में भर्ती

बीजापुर। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के मुदवेंडी गांव के जंगलों में नक्सलियों द्वारा लगाये गये आईईडी ब्लास्ट होने से डीआरजी के दो आरक्षक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं, जवानों की हालत को देखते हुए उन्हें एम्बुलेंस की मदद से देर रात मेकाज लाया गया। जहां से उन्हें रायपुर रेफर करने की बात कही गई, लेकिन खराब मौसम के चलते जवानों को आपातकाल में ही रखा गया है। दोनों जवानों के बाएं पैर में गंभीर चोंट आई है।

घायल जवानों किशन हपका और दिनेश वलवा ने बताया है कि 3 दिन का नक्सल आपरेशन था। जिसमें अलग-अलग टीम के 18 सौ से अधिक जवान ऑपरेशन पर निकले हुए थे। लगातार बारिश के चलते चलना भी मुश्किल था। हमें जो टारगेट दिया गया था, उसे देखने के बाद वापस आने के दौरान पीडिया के ओयामपारा में नक्सलियों ने आईडी लगा दिया था। जिसके बाद ब्लास्ट होने से जवान घायल हो गए। घायलों को उपचार के जिला अस्पताल लाया गया। वहां से मेकाज रेफर किया गया।

ग्रेहाउंड्स जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया, कई घायल

बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक सेमलडोडी के जंगल में तेलंगाना की ग्रेहाउंड्स फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की भी जानकारी मिल रही है। हालांकि अब तक एक नक्सली का शव और एक हथियार बरामद किया गया है। घटना की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

फिलहाल इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर उसूर ब्लॉक का सेमलडोडी गांव पड़ता है। ग्रेहाउंड्स कि टीम को खबर मिली थी कि नक्सलियों का बड़ा कैडर सेमलडोडी के जंगल में मौजूद है। इसके बाद ऑपरेशन लॉंच किया गया।

मुख्यमंत्री साय और मंत्रियों ने भरत के पार्थिव शरीर को दिया कंधा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बलिदान हुए रायपुर के रहने वाले भरत साहू के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। जवान 17 जुलाई को बीजापुर में हुए नक्सल हमले में बलिदान हो गए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत गृहमंत्री विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू समेत कई नेताओं ने माना स्थित चौथी वाहिनी बटालियन पहुंचकर बीजापुर नक्सली हिंसा में शहीद जवान भरत साहू को श्रद्धांजलि दी है। बलिदान हुए जवान की अर्थी को कंधा देने के बाद उन्हें पूरे सम्मान के साथ रायपुर स्थित उनके निवास मोवा के लिए विदा किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजपुर में 17 जुलाई को नक्सली घटना में हमारे चार जवान घायल और दो जवान शहीद हुए हैं। घायल जवानों से मुलाकात भी हुई है। सभी घायल जवान खतरे से बाहर हैं। हम शहीद जवानों की शहादत को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी।

आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, डिप्टी सीएम विजय शर्मा नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन

कबीरधाम। 18 जुलाई को बीजापुर जिले के तर्रेम क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में एसटीएफ के दो जवान भारत साहू और सतेर सिंह शहीद हो गए थे और चार जवान घायल हो गए थे। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया है। कबीरधाम जिले के कवर्धा विधायक और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस दर्दनाक घटना से आहत होकर आज 19 जुलाई को अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम ने अपने सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी अपील की है कि आज जब उनके भाई शहीद हुए हैं तब उनका मन आहत और व्यथित है, वे उनका जन्मदिन न मनाएं और इस कठिन समय में शहीद जवानों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। विजय शर्मा ने कहा कि शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और समाज और सरकार उनके अमर बलिदान को स्मरणित रखेगी। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि शहीद जवानों की आत्मा को शांति मिले और घायल जवान जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। विजय शर्मा ने कहा कि इस दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमें यह सोचने पर विवश कर दिया है कि बस्तर की सेवा के लिए हमारे जवान कितने कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस अवसर पर सुरक्षाबलों की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की और उन्हें हर संभव सहायता और साथ देने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार माओवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज करेगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। शर्मा ने कहा कि शहीद जवानों के परिवारों के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है। उन्होंने कहा कि शहीद जवानों का बलिदान देश के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है और हमें उनकी वीरता पर गर्व है। उपमुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला जन्मदिन था। शर्मा और उनके समर्थक काफी उत्साहित थे और इसके लिए जोर-शोर से तैयारियां भी की जा रही थीं। कवर्धा सहित पूरे राज्य के विभिन्न स्थानों में जन्मदिन मनाने की तैयारियां चल रही थीं, उपमुख्यमंत्री शर्मा के अपना जन्मदिन नही मनाने के निर्णय के बाद तैयारियों को अचानक रोक दिया गया है।

मलेरिया और डायरिया से हुई मौतों को लेकर हाईकोर्ट सख्त

स्वतः संज्ञान लेकर मुख्य सचिव से मांगा जवाब

बिलासपुर। कोटा क्षेत्र के टेंगनामड़ा में दो बच्चों की मलेरिया से मौत हो जाने और कांवड़ में मरीज को अस्पताल ले जाने समेत स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी दूसरे मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जनहित याचिका दर्ज करते हुए मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

आपको बता दें कि कोटा विकासखंड के टेंगनमाड़ा में 12 और 15 साल के दो भाईयों इमरान और इरफान की कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्हें 5 दिन पहले बुखार आया था। तब टेंगनमाड़ा के उप स्वास्थ्य केंद्र में उनके परिजन उन्हें उपचार के लिए ले गए थे। वहां के स्टाफ ने साधारण बुखार और ठंड की दवा देकर उन्हें वापस भेज दिया था। बाद में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। तब उन्होंने गांव के ही झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराया जिसने दोनों बच्चों को स्लाइन चढ़ाया और इंजेक्शन लगाया। लेकिन दोनों बच्चों की तबीयत सुधरने के बजाए बिगड़ गई।इसके बाद परिजनों ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया।जहां उनकी मौत हो गई।

इसके अलावा कोटा ब्लॉक में ही कांवड़ में मरीज को ढोने, सरगुजा और बस्तर संभाग में डायरिया और मलेरिया से 11 से अधिक लोगों की मौत हो जाने की घटनाएं हाल के दिनों में सामने आ चुकी हैं। इन सब घटनाओं से चिंतित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान जनहित याचिका दर्ज की है। और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने डीवीओआर टेक्नोलॉजी लगाने के लिए राज्य सरकार की सहमति के बाद नाइट लैंडिंग और जमीन सीमांकन का काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल के कड़े रुख और सार्थक दखल से बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। गुरुवार को जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर हुई बैठक में केंद्र सरकार ने जो निर्देश नाइट लैंडिंग के सम्बन्ध में दिए गए है उन्हें मानने के लिए राज्य सरकार तैयार है। इससे स्पष्ट हो गया कि अब राज्य सरकार सेटेलाइट आधारित पीबीएन टेक्नोलॉजी के आधार पर नाइट लैंडिंग सुविधा की जिद नहीं करेगी।

क्या था मामला - आपको बता दें कि लगभग एक साल से केंद्र और राज्य के बीच एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग पर मतभेद के कारण मामला अटका था। 19 जून को सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य की संयुक्त बैठक बुला कर मामले को हल करने के निर्देश दिए थे। आखिरकार राज्य को वही निर्देश मानने पड़े जो केंद्र ने अपने 18 अप्रैल के पत्र में दिए थे। उस निरर्थक बहस के कारण हुए समय के नुकसान की भरपाई के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह केंद्र सरकार की एजेंसीज के साथ मिल कर जल्दी से जल्दी डीवीओआर समेत अन्य उपकरणों के स्थापना की प्रक्रिया शुरू करे।

डायरिया से नहीं हुई तीन ग्रामीणों की मौत कलेक्टर को टीम ने सौंपी जांच रिपोर्ट

कवर्धा। कबीरधाम जिले के बोडला विकासखंड के ग्राम सोनवाही के पारा-टोला सरेंडा निवासी तीन ग्रामीणों की मृत्यु का कारण दूषित जल पीने या डायरिया से नहीं हुई है। तीन ग्रामीणों की मृत्यु का कारण अलग-अलग है। एक ग्रामीण महिला की मृत्यु रायपुर के डॉ। भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में हुई है। ये बातें कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर बनी तीन सदस्यीय जांच टीम ने कलेक्टर को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट में बताई है।

कलेक्टर जनमेजय महोबे को बोडला विकासखण्ड के ग्राम सोनवाही के आश्रित पारा-टोला सरेंडा में तीन ग्रामीणों की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग, पीएचई और अनुविभागीय अधिकारी बोडला के साथ सरेंडा गांव का अवलोकन किया था और पीड़ित परिवारों से आवश्यक चर्चा की थी। कलेक्टर ने तीन ग्रामीणों की मृत्यु की वास्तविक कारणों की जांच के लिए कार्यपालन अभियंता पीएचई, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बोडला, और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कवर्धा की तीन सदस्यीय जांच टीम बनाई थी। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी है।

जांच रिपोर्ट में बताया गया कि सरेंडा गांव में तीन ग्रामीणों की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर ग्राम सरेंडा का भ्रमण कर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की गई। पूछताछ में बताया गया कि मृतक पनकिन बाई पति नन्हुआ सिंह 75 वर्ष की थी। वह सरेंडा की निवासी थी। पिछले कुछ वर्षों से लकवा रोक से ग्रसित थी, जिसके कारण वह चलने फिरने में असमर्थ थी। धीरे-धीरे शारीरिक कमजोरी बढ़ने के कारण 14 जुलाई को दोपहर को उनकी घर पर ही मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उन्हें किसी भी प्रकार के अन्य बीमारी जैसे उल्टी-दस्त अथवा बुखार नहीं था।

मृतक सोमबाई पति सुमेर सिंह बैगा का उम्र 70 वर्ष की थी। पिछले दो वर्षों से लकवा ग्रस्त थी। उसे खाना खाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। पिछले 20 दिनों से खाना भी नहीं खा पा रही थी। ग्रामीणों के मुताबिक, 17 जुलाई को दोपहर 3 बजे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उन्हें किसी भी प्रकार की अन्य बीमारी जैसे उल्टी-दस्त अथवा बुखार नहीं था। मृतक अनिता बैगा पिता महासिंह उम्र 29 वर्ष की थी। वह 6 माह की गर्भवती थी। उन्हें उल्टी-दस्त बुखार एवं रक्त स्त्राव की समस्या के साथ 14 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झलमला में भर्ती कराया गया। स्थिति में सुधार नहीं होने के कारण उसी दिन उन्हें जिला अस्पताल कवर्धा में रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उनका स्वास्थ्य सुधार नहीं होने के कारण उसे डॉ। भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में भर्ती किया गया। उपचार के दौरान 17 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु का कारण डायरिया या उल्टी दस्त नहीं हैं। उनकी मृत्यु का कारण सेप्टीक शॉक विथ एक्यूट किडनी इन्ज्यूरि विथ सर्वेयर मेटाबूलिक एसिडोसिस एण्ड एक्यूट गैस्ट्रोएन्टेराइटिस विथ आईयूडी बताया गया है।

कलेक्टर जनमेजय महोबे ने बताया कि ग्राम सरेंडा में स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य शिविर लगाकर सभी महिला-पुरूष एवं बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है। यह परीक्षण आगे भी चलता रहेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में ग्रामीणों को उनके स्वास्थ्य के आधार पर दवाई दी जा रही है। सरेंडा गांव और आसपास के सभी क्षेत्रों में बोडला एसडीएम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीएमओ लगातार दौरा कर रहे हैं।

पीएचई विभाग ने पानी की गुणवत्ता जांची

बीजापुर। बीजापुर के भोपालपटनम ब्लॉक के तारलागुड़ा में संचालित कन्या आवासीय विद्यालय पोटाकेबिन, बालक आवासीय विद्यालय पोटाकेबिन व आरएमएसए बालक बालिका पोटाकेबिन के सैकड़ों बच्चे दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया। खबर के बाद विभाग हरकत में आया और गुरुवार को भोपालपटनम पीएचई की टीम तारलागुडा पहुंची। टीम ने पोटाकेबिनों की जांच कर पानी की गुणवत्ता जांची। भोपालपटनम में पदस्थ पीएचई उप अभियंता बीआर बंजारे ने बताया कि जांच में पाया गया है कि आश्रमों में लगे बोरिंग का पानी खराब है। इसमें आयरन की मात्र अधिक हैं। वह पीने योग्य नहीं हैं। इसके लिए पोटाकेबिन के अधीक्षकों को बताया गया हैं कि यहां का पानी पीने योग्य नहीं है। इसका उपयोग कपड़े धोने नहाने व अन्य काम में कर सकते हैं। फिलहाल पोटाकेबिन में पीने के लिए पानी पुलिस थाने से लेकर उपयोग किया जा रहा हैं। बता दें कि पोटाकेबिन तारलागुडा मे फिल्टर प्लांट लगा हुआ हैं। लेकिन वह एक साल से खराब पड़ा हुआ हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बस्तर में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें मकान गिरने से दो मासूम दबे

सुकमा। सुकमा जिले में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण सुकमा जिले के गांवों में कई कच्चे मकान धराशायी हो गए। इस दौरान एक गांव में कच्चा मकान गिरने से मलबे में 2 मासूम बच्चे दब गए। जिन्हें परिजनों और ग्रामीणों ने बाहर निकाला। घर गिरने और मकान दबने की जानकारी सुकमा कलेक्टर तक पहुंची । जिसके बाद सुकमा कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक कार्रवाई और उपचार करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पोलमपल्ली के अतुलपारा में पहुंची। इसके बाद गांव से स्वास्थ्य विभाग की टीम इस घटना में घायल हुए 2 मासूमों को लेकर पोलमपल्ली अस्पताल पहुंची। जहां बच्चों को अस्पताल में भर्ती करके उपचार किया जा रहा है।फिलहाल बच्चों की स्थिति खतरे के बाहर बताई जा रही है। फिलहाल अस्पताल में कोंटा बीएमओ सिद्धार्थ, डॉ। वेद प्रकाश साहू और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि बस्तर में बीते 3 दिनों से लगातार धीमी गति से बारिश हो रही थी।

दो दिव्यांग को मुख्यमंत्री के निर्देश पर मिला ट्राई सायकल

महासमुंद। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांग को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राई सायकिल उपलब्ध कराया गया है। बैटरी चलित ट्राई सायकिल पाकर दिव्यांग टिकेश्वर और गौरी ने मुख्यमंत्री श्री साय और जिला प्रशासन का आभार जताया है। महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखण्ड के ग्राम अठारहगुड़ी के रहने वाले 34 वर्षीय दिव्यांग श्री टिकेश्वर पटेल और ग्राम रेमडा निवासी 30 वर्षीय गौरी खंडेल कलेक्टर श्री प्रभात मिलक के हाथों ट्राई साइकिल पाकर वे दोनों बहुत खुश हैं। दोनों दिव्यांगों को पहले आने-जाने के लिए परिजन या किसी व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता था। मोटराईज्ड ट्रायसायकल मिल जाने से अब उन्हें गांव या गांव से बाहर आने-जाने में आसानी होगी। दिव्यांग टिकेश्वर पटेल ने बताया कि अब उन्हें अपने व्यवसाय के द्वारा आर्थिक स्थिति में और सुधार करने का मौका मिलेगा। इसी तरह गौरी खंडेल ने कहा कि मोटराइज्ड ट्राई साइकिल मिलने से मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिला है।

गुम तीन नाबालिग किशोरियों को पुलिस ने किया बरामद

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में गुम तीन नाबालिग किशोरियों को जम्मू, कोरबा और जांजगीर से पुलिस ने बरामद किया है। नाबालिग बालिकाओं को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। मामला जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है जहां मिली जानकारी के अनुसार जिले के पुलिस अधिकारी विवेक शुक्ला ने निर्देशन में जिले में गुम/अपहृत बालक/बालिकाओं की बरामदगी को लेकर निर्देशन पर हमर पुलिस हमर संग के तहत पता तलाश किया जा रहा है। नवागढ़ थाना में धारा 363 एपीसी के तहत नाबालिक बालिका की गुम (अपहृत) का मामला दर्ज था। 2 साल पहले घर से बिना बताया चली गई थी जिसमे लोकेशन के आधार पर जम्मू से एक नाबालिक बालिका बरामद किया गया है। वही कोरबा से एक नाबालिक बालिका और जांजगीर से एक नाबालिक बालिका को बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।

रजाई की दुकान में लगी आग लाखों का सामान हुआ खाक

जांजगीर चांपा। जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ में जयपुरी सोफा रिपेयरिंग और रजाई दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। दुकान के अंदर रखा समान जलकर खाक हो गया है। 20 हजार नगद सहित पांच लाख का नुकसान हुआ है। शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आग लगने की सूचना पामगढ़ पुलिस और दमकल की टीम को दी गई। घटना पोस्ट ऑफिस के बगल पामगढ थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार, मोहम्मद वकील निवासी दरभंगा बिहार जोकि 15 वर्षों से पामगढ़ में रहकर रजाई गद्दा बनाने और बेचने का काम कर करते हैं। आज सुबह जयपुरी सोफा रिपेयरिंग एवं रजाई दुकान में अचानक से आग लग गई। मौके पर काम कर रहे और आसपास के लोगों ने देखा। लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। मगर दुकान आग तेजी से फैल गई। दुकान के अंदर रखे सोफा के समान ओर रजाई गद्दा के साथ 20 हजार रुयये नगदी रकम भी जल गया। मोहम्मद वकील को आर्थिक नुकसान हुआ है, जोकि 5 लाख रुपये से अधिक है।

धरमपुरा में पाया गया जेई का मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

जगदलपुर। जगदलपुर में जेई (जेपेनीज इंसेफ्लाइटिस) रोग से पीड़ित एक बच्चा मिला है। धरमपुरा में रहने वाले एक 12 वर्षीय बच्चे में जेई के लक्षण पाया गया, जिसे बेहतर उपचार के लिए मेकाज में भर्ती किया गया। जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्चे के साथ ही परिजनों का भी टेस्ट कराया गया है। मामले की जानकारी देते हुए जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सी मैत्री ने बताया कि जगदलपुर जेई का पहला मरीज शहर के धरमपुरा में मिला है। जेई के लक्षण 12 साल के स्कूली बच्चे में पाए गए है। मेकाज में बच्चे का इलाज चल रहा है, जेई बच्चों के लिए काफी घातक है। जेपेनीज इंसेफ्लाइटिस मच्छर के काटने से होने वाला एक ऐसा दुर्लभ संक्रमण है जो लगभग दो लाख लोगों में से किसी एक आदमी में पाया जाता है। जेपेनीज इंसेफ्लाइटिस को आमतौर पर जापानी बुखार के नाम से भी पहचाना जाता है, यह एक तरह का दिमागी बुखार होता है जो वायरल संक्रमण की वजह से होता है।

जंगली सुअर और हिरण के शिकार पर वन विभाग ने दी दबिश

■ शिकारी हुआ फरार, जंगली सुअर और हिरण का अवशेष बरामद

कोरबा। कोरबा में जंगली जानवरों का शिकार कर शिकारी फरार हो गए। वन विभाग की टीम ने बंद घर का ताला तोडक़र जब दबिश दी शिकारी तो नही मिले लेकिन जंगली सूअर और चीतल के अवशेष बरामद जरूर किये। कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र पाली के मुनगाडीह परिसर के अधीन आने वाले ग्राम दमिया में अवैध शिकार करने की सूचना वनमंडलाधिकारी कुमार निशांत को मिली थी। उन्होंने तत्काल पाली रेंजर को निर्देशित कर टीम गठित किया और उप वनमंडलाधिकारी पाली के नेतृत्व में ग्राम दमिया में उक्त स्थान पर दबिश दी गई। अमले के पहुंचने से पहले शिकारी फरार हो गए और उक्त घर में ताला लगा हुआ मिला।

पाली रेंजर संजय लकड़ा ने बताया कि जंगली मांस बेचे जाने की सूचना के आधार पर जहां घर पर ताला बंद था जहां पुलिस को सूचना दी गई जिसकी मौजूदगी में ताला तोड़ा गया कमरे के अंदर से मांस और हथियार मिले हैं जिसे जब्त किया गया है आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। रेंजर की माने तो आरोपी को पकड़ने मुखबीर लागये गए हैं बहुत जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे।

घर के भीतर से 1 जंगली सुअर का शव 38 किलो, 9 बंडल सेटिरंग तार, 2 नायलोन जाल, 1 नग फरसा, 1 प्लास्टिक बोरी खून सना हुआ, 2 नग लकड़ी का गुटका, चीतल का मांस कटा हुआ बाल्टी में 16 किलो एवं बोरी में 38 किलो, नायलोन का जाली 2 गुच्छा, चीतल का सींग 4 नग, 1 नग चीतल का सिर ढाई किलो, 2 बंडल बिजली तार, 1 नग कुल्हाड़ी, 1 हीरो स्प्लेंडर दुपहिया वाहन क्रमांक- सीजी 10 बीएच 0370 जप्त किया गया।

डीएफओ ने बताया कि मुख्य आरोपी महेन्द्र गंधर्व पिता संतराम गंधर्व, सुरेन्द्र गंधर्व पिता संतराम गंधर्व, महावीर गंधर्व पिता धर्मेन्द्र, विरेन्द्र गंधर्व पिता संतराम गंधर्व सभी निवासी ग्राम दमिया पर वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही कर तलाश की जा रही है। जप्त जंगली सूअर एवं चीतल के मांस पशु चिकित्सक पाली के द्वारा पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कार्यवाही में मुख्य रूप से परिक्षेत्र अधिकारी पाली, यशमन कुमार आडिल, दीपक कुमार पटेल, राजेश कुमार धिरही, श्रीमती सविता पटेल, श्रीमती अनिता कुंवर, विरेन्द्र कुमार, नंदकिशोर सिंह आरआई, शिवकुमार डहरिया, पुलिस थाना पाली के साथ संयुक्त कार्यवाही किया। उपरोक्त अपराधी की सूचना प्राप्त होने पर मोबाइल नंबर 6264557647 अथवा 8319774533 पर सूचना देने पर उचित ईनाम दिया जावेगा।

एक घंटे की बारिश ने खोली शहर की पोल

■ निचली बस्तियों में भरा पानी, पेड़ हुआ धराशाई

जगदलपुर। जगदलपुर में शुक्रवार की सुबह शहर में एक घण्टे हुई झमाझम बारिश ने शहर की पोल खोल दी है। एक ओर जहां निचले इलाके में बसे घरों में पानी भर गया, वही शहर के बीच स्थित कोतवाली थाना में लगे विशालकाय पेड़ भी धराशाही हो गया, इस घटना में कोतवाली थाना में मौजूद जब्त गाड़ियां भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

बता दें कि विगत कुछ दिनों से बरसात होने की बात कही जा रही थी, इसके अलावा रिमझिम बारिश भी हो रही थी, लेकिन अचानक से शुक्रवार की सुबह हुई झमाझम बारिश से शहर के केवरामुण्डा, आकाश नगर, पनारा पारा, तेतरकुटी, महादेवघाट, गंगानगर, दलपतसागर, वीर सावरकर वार्ड आदि इलाको में पानी भर गया, लोग सुबह से बाल्टी या अन्य माध्यमो से पानी को बाहर निकालने में जुट गए, कई जगह तो कार भी आधा डूब गया, इसके अलावा कई जगहों में बारिश का पानी ज्यादा भर जाने से स्कूल की छुट्टी भी दे दिया गया, साथ ही शासकीय क्वाटर के दीवार भी धराशाही हो गए। बता दे कि कोतवाली थाना परिसर में सायबर आफिस के सामने पुलिस द्वारा जब्त गाड़ियों को खड़ा किया गया था, लेकिन विशालकाय पेड़ के गिरने से गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वही पेड़ को काटने का काम भी शुरू कर दिया गया है।

शुक्रवार सुबह बड़ाजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चुन्डीमेटावाडा में एक व्यक्ति तालाब में डूब जाने पर जिले का बाढ़ बचाव टीम रवाना किया गया, टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर सर्चिंग अभियान चलाया गया और लगभग डेढ़ से 2 घंटे बाद सनू पोयम 70 वर्ष के शव को निकाल पुलिस को सुपुर्द किया गया। एक घण्टे की बारिश से हर तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, शहर की सड़कों से लेकर गावों तक निचले इलाके डूबे हुए है, कई इलाकों में तो बिजली बिल भी गुल है, जिसके कारण आमजन परेशान है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल हरिचंदन को पार्षद प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से

शुक्रवार को राजभवन में रायपुर नगर निगम रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर एवं अन्य सदस्यों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने निगम क्षेत्र के अंतर्गत शारदा चौक के पास प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य के लिए राज्यपाल से उचित पहल करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर पूर्व महापौर व नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे, रितेश त्रिपाठी, ज्ञानेश शर्मा, कुमार मेनन, श्रीमती अंजनी राधेश्याम विभार, श्रीमती द्रौपती हेमंत पटेल एवं अन्य पार्षद उपस्थित थे।

कांग्रेस ने बनाई 24 जुलाई को विधानसभा घेराव की रणनीति

रायपुर। 24 जुलाई को विधानसभा घेराव

करने की रणनीति बनाने कांग्रेस नेताओं-कार्यकर्ताओं की कांग्रेस भवन में बैठक हुई. पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने 20 हजार से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बदहाल है। जनता सड़क पर उतर प्रदर्शन करेगी। मंडी गेट में आमसभा के बाद विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे। कांग्रेस का आंदोलन ऐतिहासिक होगा। इस दौरान डॉ. खूबचंद बघेल के नाम की योजना बदले जाने को लेकर दीपक बैज ने कहा कि योजना का नाम बदलना ठीक नहीं है। समाज ही नहीं प्रदेश के लोगों में भी इसे लेकर नाराजगी है। भाजपा सरकार समाज को बांटने का काम कर रही है।

रिश्वत लेते स्वास्थ्य विभाग का बाबू गिरफ्तार

रायपुर। अपने ही अधीनस्थ विभागीय कर्मी से रिश्वत लेना बाबू को महंगा पड़ गया। दरअसल स्वास्थ्य विभाग का बाबू सूरज नाग को एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मामला ये था कि सूरज नाग ने स्टाफ नर्स से दो साल के अध्ययन अवकाश के एवज में 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी ।एसीबी ने बाबू को राजेंद्र नगर विजेता कॉम्प्लेक्स स्थित घर के पास रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। नियमागत आगे की कार्रवाई बाबू को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी ने शुरू कर दी है।

मंत्री केदार कश्यप ने अरपा भैंसाझार परियोजना प्रगति की समीक्षा की

बिलासपुर। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप

ने अरपा भैंसाझार परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारीयों को हर हाल में इसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। कश्यप ने 4.15 करोड़ से बने निरीक्षण गृह का भी लोकार्पण किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाये। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि अरपा भैंसाझार परियोजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। राज्य सरकार इसे किसानों के हित में जल्द से जल्द पूरा कराना चाहती है। इसमें आने वाली गतिरोध को दूर करना अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की संयुक्त जवाबदारी है।

टमाटर हुआ 100 रुपये किलो, फुटकर व्यापारी कम कीमत पर बेचने तैयार नहीं

रायपुर। राजधानी रायपुर में वैसे तो लोग तेज

गर्मी से परेशान हैं और ऊपर से सब्जियों में डलने वाला लाल टमाटर उन्हें रुला रहा है। पिछले दिनों जहां 70 से 80 रुपये किलो में यह बिका और स्थानीय बाजार में शुक्रवार को टमाटर 100 रुपए किलो तक पहुंच गया। फुटकर व्यापारी इससे कम कीमत पर टमाटर बेचने तैयार नहीं है और उनका कहना हैं कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में और उछाल आने की संभावना है। हरी सब्जियों के शौकीन लोगों को टमाटर का स्वाद नहीं मिल रहा है वहीं गृहणियों के लिए बिना टमाटर सब्जी-तरकारी तैयार करना मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह यह है कि गैर छत्तीसगढ़ी प्रांत से पहुंच रहे टमाटर की खेप में गिरावट आ गई है, वहीं स्थानीय बाडियों में भी टमाटर की फसल अभी शुरू हुई है। ऐसे में अगले एक-दो महीने तक टमाटर के दाम में काफी उछाल रहेगा। शुक्रवार को जहां टमाटर 100 रुपये किलो तक पहुंच रहा हैं और इसकी कीमतों को सुनकर ग्राहक उल्टे पांव लौट रहे हैं। टमाटर के अलावा करेला, बरबट्टी, गंवार फल्ली जैसी अन्य सब्जियों की कीमतें भी दिन-ब-दिन बढ़ रही है।

अटल ने पृथक राज्य बनाकर दिया, इसे संवारने की जिम्मेदारी हमारी : साय

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के स्वप्नद्रष्टा थे डॉ. खूबचंद बघेल, 124वीं जयंती समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के डॉ. खूबचंद बघेल व्यावसायिक परिसर, फूल चौक में आयोजित डॉ. खूबचंद बघेल की 124वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने डॉ. खूबचंद बघेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने डॉ. खूबचंद बघेल का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा थे। एक अच्छे डॉक्टर और साहित्यकार के रूप में उनकी अलग पहचान थी। मुख्यमंत्री श्री साय ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर हमारे पुरखों का सपना पूरा किया। हम सभी अटल जी के आभारी हैं। अब इस राज्य को संवारने की जिम्मेदारी हम सभी की है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से सरकार के मुखिया का दायित्व मुझे मिला है। हमारी सरकार ने प्रदेश में 7 माह पूरे किए हैं और सरकार बनने के दूसरे ही दिन हमने 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का काम किया। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की। 13 लाख किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस का अंतरण, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक माताओं-बहनों को हर महीने एक-एक हजार रुपए सालाना 12 हजार रूपए की सहायता राशि के साथ ही तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए संग्रहण दर 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए प्रति मानक बोरा करने जैसे कई अहम निर्णय लिए हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने जिस छत्तीसगढ़ का सपना देखा है, उसे आकार देने के लिए हम सभी कार्य कर रहे हैं। हमारे पास खनिज संपदा भरपूर मात्रा में है। हमारे पास कोयला, आयरन, बॉक्साइट, गोल्ड, डायमंड जैसे खनिज उपलब्ध हैं। मिनरल्स के क्षेत्र में भी हमारा छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध है। तरह-तरह के वनोपज हमारे छत्तीसगढ़ की शोभा बढ़ाते हैं, जिनके वैल्यू एडिशन से हम वनवासी भाइयों-बहनों के जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बना रहे हैं। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने उपस्थित लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि हम समाज और प्रदेश के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाएं । डॉ. खूबचंद बघेल ने समाज में भेदभाव को मिटाने के लिए और गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का काम किया।

छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यकारी अध्यक्ष श्री के के नायक ने डॉ. खूबचंद बघेल के प्रारंभिक जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और सामाजिक उत्थान के लिए उनके योगदानों के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर श्री रघुनंदन वर्मा, श्री दशरथ वर्मा सहित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के पदाधिकारीगण और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

माओवादी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं हमारे जवान: साय

मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास से लौटते ही सीधे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचकर घायल जवानों का हाल-चाल जाना

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय अपने दिल्ली दौरे से लौटने के तुरंत बाद बीजापुर जिले के तर्रेम क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में घायल एसटीएफ के 4 जवानों को देखने रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा भी साथ थे।मुख्यमंत्री श्री साय ने घायल जवानों का हाल- चाल जाना और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए दो जवानों को नमन करते हुए कहा की हम माओवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। उन्होंने घायल जवानों के अदम्य साहस की प्रशंसा की और उनका मनोबल बढ़ाया। उल्लेखनीय है की गुरुवार को बीजापुर जिले के तर्रेम क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में एसटीएफ के 2 जवान शहीद और 4 जवान घायल हो गए थे। घायल जवानों को उनके बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है।

उपमुख्यमंत्री शर्मा के क्षेत्र के जिला चिकित्सालय को मिला रेडियोलॉजिस्ट

कबीरधाम। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के अथक प्रयासों से कबीरधाम जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कबीरधाम जिला अस्पताल के लिए रेडियोलॉजिस्ट डॉ. वी. गोपाला कृष्णा को एनएचएम (संविदा) के पद पर शर्तो के अधीन नियुक्ति प्रदान की है। इस सबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति से अब मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कबीरधाम जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार और विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल से विशेष अनुरोध किया था।

जिला चिकित्सालय में रेडियालॉजिस्ट की नियुक्ति से सुविधाओं में विस्तार होगा। रेडियोलॉजिस्ट के होने से मरीजों की बीमारियों का सही समय पर और सटीक निदान हो सकेगा। इससे उपचार की प्रक्रिया में सुधार होगा। स्थानीय स्तर पर रेडियोलॉजिस्ट की उपलब्धता से मरीजों को बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और पैसे की बचत होगी। आपातकालीन स्थिति में रेडियोलॉजिस्ट की उपस्थिति से तत्काल जांच और उपचार संभव होगा, जिससे मरीज की जान बचाई जा सकती है। रेडियोलॉजिस्ट की विशेषज्ञता से जटिल मामलों में भी सही निदान और उपचार की योजना बनाई जा सकती है। रेडियोलॉजिस्ट के माध्यम से रोग की पहचान तेजी से होती है, जिससे इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है। इन सभी लाभों के कारण जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

जीवन व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी खत्म करने की मांग

सांसद ज्योत्सना और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मिले महापात्र

रायपुर। जीवन व स्वास्थ्य बीमा पालिसी कोई उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा के लिए एक किस्म की जोखिम से अपने और अपने परिवार की रक्षा है। लेकिन इस पर 18त्न तक जीएसटी लगाए जाने से आम लोगों पर आर्थिक भार बढ़ता है। इस पर जीएसटी खत्म करने के लिए जीएसटी काउंसिल में पहल के लिए सीजेडआईईए के महासचिव धर्मराज महापात्र ने आरडीआईईयू के महासचिव सुरेंद्र शर्मा के साथ सांसद ज्योत्सना महंत के साथ प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

बीमा कर्मियों के अखिल भारतीय संगठन आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन के आह्वान पर संसद के बजट सत्र के पूर्व देशभर में सांसदों से मुलाकात कर बीमा उद्योग में व्याप्त समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से बीमा प्रीमियम से जीएसटी हटाने, बीमा पालिसी धारकों के लिए आयकर छूट में आकर्षक प्रावधान करने, राष्ट्रीयकृत आम बीमा की चारों कंपनियों को एकीकृत करने तथा एलआईसी का विनिवेशीकरण रोके जाने की मांग की गई है।

ज्ञापन में कहा गया है कि जीवन बीमा व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियमों पर 18त्न जीएसटी से पालिसी धारकों पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है, और इससे व्यवसाय में वृद्धि प्रभावित हो सकती है। भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के नेतृत्व में पिछले कार्यकाल में गठित संसद की वित्त संबधी संसदीय स्थाई समिति ने भी इन दरों को तर्कसंगत बनाये जाने की सिफारिश की है। इसलिए इस बजट में बीमा प्रीमियम से जीएसटी वापस लिये जाने की जरूरत है।

भारत में घटती घरेलू बचत के मद्देनजर जीवन बीमा के माध्यम से हो रही बचत को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है, इसलिए बजट में बीमा प्रीमियमों हेतु आकर्षक प्रावधान करते हुए आयकर में छूट बढ़ाई जानी चाहिए। जीवन बीमा के माध्यम से एकत्रित प्रीमियम से सरकार को दीर्घकालीन निवेश हेतु एकमुश्त राशि उपलब्ध होती है, जो देश के बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के विकास में लगाई जाती है। इसी प्रकार राष्ट्रीयकृत आम बीमा निगम की चारों कंपनियों को एकीकृत कर उन्हें मजबूत किए जाने की जरूरत है, जिससे वे आपसी प्रतिस्पर्धा से हटकर निजी कंपनियों का मुकाबला करने में और अधिक सक्षम हो सके।

मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में देश के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान एलआईसी के 3 ।5त्न शेयरों का विनिवेशीकरण कर इसे स्टाक मार्केट में सूचीबद्ध कर दिया था। इस महत्वपूर्ण संस्थान से सरकारी अंशधारिता कम करते जाने से देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता ही खतरे में पड़ सकती है। अत: एलआईसी के विनिवेशीकरण को यही पर रोक दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री एवं सांसद महंत ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यान से सुना तथा संसद सत्र के दौरान इन मुद्दों को उचित रूप से प्रस्तुत किये जाने का आश्वासन दिया।

गन्ना किसान नाराज, हाईवे में चक्काजाम की तैयारी

150 करोड़ रुपये का भुगतान

कबीरधाम। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन

कबीरधाम जिले में होता है। जिले में हर साल करीब 35 हजार हेक्टेयर में गन्ना की फसल ली जाती है। जिले के गन्ना किसान अपने फसल को कवर्धा विधानसभा अंतर्गत ग्राम राम्हेपुर स्थित भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना व पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिशेसरा स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में बेचते है। लेकिन, हैरानी की बात है कि इन दोनों कारखाना में गन्ना बेचने के सात माह बाद किसानों का करीब 150 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है।

ऐसे में जिले के किसान नाराज है। किसानों की समस्या को लेकर पंडरिया शक्कर कारखाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व भोरमदेव शक्कर कारखाना में समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ ने ज्ञापन सौंपा है। पंडरिया में ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस नेता नवीन जायसवाल, रवि चंद्रवंशी, आंनद सिंह ने बताया कि इस कारखाना में करीब 80 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है। इसमें 32 करोड़ मूल भुगतान, 33 करोड़ रुपए लाभांश राशि व 18 करोड़ बोनस राशि कुल मिलाकर लगभग 80 करोड़ रुपए बकाया है।

इसी प्रकार समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ के जिला अध्यक्ष सोनी वर्मा ने बताया कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में भी किसानों का करीब 70 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें 24.50 करोड़ रुपए बोनस, 8 करोड़ रुपए मूल भुगतान व 35.77 करोड़ रुपए रिकवरी राशि शामिल है। दोनों कारखाना में 150 रुपए किसानों का बकाया है। आने वाले 7 दिन के भीतर किसानों को यह राशि नहीं दी जाती तो नेशनल हाईवे पर चक्काजाम किया जाएगा।

हाई-हायर सेकण्डरी स्कूल की द्वितीय मुख्य परीक्षा 23 से

प्रदेश में बनाए गए 227 परीक्षा केन्द्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी स्कूल की द्वितीय मुख्य परीक्षा 23 जुलाई 2024 से 12 अगस्त तक आयोजित होगी। परीक्षा के सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर आनलाइन प्रषिक्षण उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। माशिमं की अध्यक्ष रेणु जी पिल्ले और सचिव पुष्पा साहू के मार्गदर्शन में 15 और 16 जुलाई को उक्त प्रषिक्षण संपन्न हुआ, जिसमें राज्य के सभी 227 परीक्षा केन्द्रों से केन्द्राध्यक्ष शामिल हुए।

उन्मुखीकरण में मुख्य रूप से परीक्षा पूर्व तैयारी, परीक्षा के दिन की कार्यवाही परीक्षा समाप्ति के बाद की कार्यवाही किस प्रकार से किया जाना है, इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। परीक्षा केन्द्र में विभिन्न मुख्य व्यवस्था बिजली, पेयजल और प्रसाधन की उचित व्यवस्था,मुख्य द्वार पर बैठक व्यवस्था की जानकारी का नोटिस बोर्ड, प्रतिदिन छात्र संख्या अनुसार पुलिस व्यवस्था, सूचना पटल पर आवष्यक सूचना, समय-सारणी लगाना, उत्तर पुस्तिका के बंडल तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री की समुचित मात्रा, स्थायी केन्द्र निरीक्षण पंजी का संधारण, 40प्रतिषत या उससे अधिक नि:षक्तता वाले परीक्षार्थियों को लेखक की नियमानुसार पात्र परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था पर प्रशिक्षण दिया गया।

अकारण बार-बार परीक्षार्थियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं दिया जाना, उपस्थिति पत्रक पर छात्र एवं पर्यवेक्षक का प्रतिदिन हस्ताक्षर अनिवार्यत: लिया जाना, एक ही कक्ष में विभिन्न विषयों की परीक्षा के प्रश्नपत्रों का सावधानीपूर्वक वितरण कमरे में पूर्ण शांति एवं अनुशासन बनाये रखना, अनुचित साधनो के प्रयोग को सजगता से रोकथाम किये जाने के लिए आष्यक निर्देष दिये गये। सभी उत्तर पुस्तिकाओं में द्वितीय मुख्य परीक्षा2024 की सील अनिवार्य रूप से लगानेका निर्देश दिया गया। उन्मुखीकरण का प्रस्तुतीकरण सहायक प्राध्यापक प्रीति शुक्ला के द्वारा किया गया।

विश्व की 5 सबसे बड़ी खदानों में छत्तीसगढ़ की 2 खदानें शामिल

एसईसीएल की गेवरा और कुसमुंडा बनीं दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी खदानें

बिलासपुर। विश्व की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में छत्तीसगढ़ की दो खदानों को स्थान मिला है। एसईसीएल की गेवरा और कुसमुंडा खदानों को, वर्ल्डएटलस डॉटकॉम द्वारा जारी दुनिया की टॉप 10 कोयला खदानों की सूची में क्रमश: दूसरा और चौथा स्थान मिला है। कोरबा जिले में स्थित एसईसीएल के इन दो मेगाप्रोजेक्ट्स द्वारा वर्ष 23-24 में 100 मिलियन टन से अधिक का कोयला उत्पादन किया गया जोकि भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10त्न है।

एसईसीएल की गेवरा माइन की वार्षिक क्षमता 70 मिलियन टन की है। वित्तीय वर्ष 23-24 में खदान ने 59 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है। 1981 में शुरू हुई इस खदान में 900 मिलियन टन से अधिक का कोयला भंडार मौजूद है।

इन खदानों में कोयला खनन के लिए विश्व-स्तरीय अत्याधुनिक मशीनों जैसे सरफेस माइनर का प्रयोग किया जाता है। यह मशीन ईको-फ्रेंडली तरीके से बिना ब्लास्टिंग के कोयला खनन कर उसे काटने में सक्षम है। ओवरबर्डन (मिट्टी और पत्थर की ऊपरी सतह जिसके नीच कोयला दबा होता है) हटाने के लिए यहाँ बड़ी और भारी एचईएमएम (हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी) को प्रयोग में लाया जाता है जिसमें 240-टन डंपर, 42 क्यूबिक मीटर शॉवेल एवं पर्यावरण-हितैषी ब्लास्ट-फ्री तरीके से ओबी हटाने के लिए वर्टिकल रिपर आदि मशीनें शामिल हैं। कुसमुंडा खदान द्वारा भी वित्तीय वर्ष 23-24 में 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन हासिल किया गया है और गेवरा की बाद ऐसा करने वाली यह देश की केवल दूसरी खदान है। इस अवसर पर एसईसीएल सीएमडी डॉ प्रेम सागर मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की माटी के लिए यह अत्यंत ही गौरव का विषय है कि विश्व की 5 सबसे बड़ी खदानों में राज्य कि दो खदानों को स्थान मिला है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, सेतु मण्डल रायपुर (छ.ग)

ज्ञाप क्र.   /   /सा/2024   रायपुर, दिनांक   /07/2024

निविदा सूचना (चतुर्थ आमंत्रण)

(निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 25.07.2024, समय-17:30 बजे तक)

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है:-

एन.आई.टी.क्र./ सिस्टम टेन्डर नं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू. लाख में)
1	2	3
24/156202	जिला-सुकमा के नगर पंचायत कोंटा से उड़ीसा पहुंच मार्ग के कि.मी. 1/8-10 शबरी नदी पर मोटूघाट पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के पहुंचमार्ग में डामरीकरण का कार्य।	रू. 88.31 लाख

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी https://eproc.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है।

अधीक्षण अभियंता
लो.नि.वि सेतु मण्डल, रायपुर (छ.ग.)

जी-242501164/4

संविधान नहीं, खतरे में है विपक्ष का मुस्लिम वोट बैंक

योगेन्द्र योगी

इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल केंद्र की भाजपा सरकार पर संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। मोदी सरकार ने इसके जवाब में विपक्ष पर सीधे हमला बोलते हुए 1977 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दिन 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में सरकारी स्तर पर मनाने का फैसला कर दिया। दरअसल विपक्ष जिसे संविधान खत्म करने की साजिश बता रहा है, वह दरअसल मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने की कवायद है। तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार ने अभी तक एक भी ऐसा काम नहीं किया है, जिससे लगता हो कि सरकार के इरादे संविधान को खत्म करने के हैं। इस संबंध में विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, वह दरअसल संविधान खतरे में नहीं बल्कि उनका मुस्लिम वोट बैंक खतरे में पड़ गया है। विपक्ष इसे सीधे स्वीकार नहीं करके संविधान खात्मे की संज्ञा दे रहा है। केंद्र सरकार ने जब-जब देश के मुस्लिमों की भलाई के लिए निर्णय लिया और कानून बनाया तब-तब विपक्षी दलों ने कठमुल्लाओं की भाषा बोलते हुए इसका विरोध किया है। मुस्लिम सुधारों के इस प्रयास को ही गैर भाजपा विपक्ष संविधान को खत्म करने की साजिश करार दे रहा है, हिन्दू वोट बैंक के भय से इस पर खुल कर बोलने से बच रहा है। यही वजह है कि भाजपा गठबंधन लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भी विपक्ष एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सका जिससे लगे कि देश का संविधान या आम लोगों के अधिकार खतरे में हैं। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को अधिक और कानूनी बराबरी के अधिकार सम्पन्न बनाने का ही काम किया है। यह विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा है। 17वीं लोकसभा के दौरान मणिपुर हिंसा के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी। संसद की कार्रवाई लगातार बाधित करने के कारण तत्कालीन 140 विपक्षी सांसदों की सदस्यता निलंबित की गई। विपक्ष ने इस घटना पर भी संविधान के खात्मे की दलील दी। इसके विपरीत हाल ही में तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया, इस पर इंडिया गठबंधन के दल मौन साधे रहे। केंद्र सरकार ने मुस्लिमों और देश की एकता-अखंडता को लेकर किए गए सकारात्मक प्रयासों को विपक्षी दलों ने अल्पसंख्यक वोट बैंक के नजरिए से देखा है। 3 तलाक को गैर-कानूनी बनाने के लिए मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 के पक्ष में सबसे ज्यादा वोटिंग के साथ पारित होने पर कांग्रेस ने विरोध स्वरूप वॉकआऊट किया। इससे पहले जनता दल (यूनाइटेड) और तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) के सांसदों ने भी तत्काल तलाक को अपराध बनाने वाले बिल के विरोध में वॉकआऊट किया था। इस कानून को बनाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। कांग्रेस गठबंधन के कई दलों ने एक कदम आगे बढ़ कर केंद्र में सत्ता में आने पर 3 तलाक को प्रतिबंधित करने के कानून को खत्म करने का वादा किया था। इससे साफ जाहिर है कि विपक्षी दलों की मंशा मुस्लिम महिलाओं को पाषाण युग जैसा जीवन जीने के लिए अभिशप्त करने की रही। गौरतलब है कि शाहबानो वाले मामले में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक बनाए रखने के लिए कानून में संशोधन करके इस आदेश को रद्द कर दिया था। इसी तरह केंद्र सरकार ने जब जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद की धारा 370 हटाने का निर्णय लिया, तब भी विपक्षी दलों को मुस्लिम वोट दरकता नजर आया। विपक्षी दलों ने देश की एकता-अखंडता को मजबूत करने और जम्मू-कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाले इस कानून का भरसक विरोध किया। यह बात दीगर है कि इस कानून के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर विकास के मामले में बुलंदी छू रहा है। धारा 370 हटने से पहले देश से कटा यह राज्य अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुका है। मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर भी विपक्षी दलों को मानो सांप सूंघ गया हो। इस निर्णय के मुताबिक कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सी.आर.पी.सी. की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मिलने की हकदार है। इस वजह से वह गुजारे भत्ते के लिए याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भरण-पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है।

आगे बढ़ने को तैयार भाजपा

मृत्युंजय दीक्षित

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, भाजपा ने लोकसभा चुनावों में सभी 80 सीटों पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था किंतु अधूरा रह गया और भाजपा को मात्र 37 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। स्थिति इतनी प्रतिकूल हो गई कि अयोध्या विधानसभा सीट वाली फैजाबाद संसदीय सीट पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। स्वाभाविक है भाजपा को गहरा धक्का लगा और पारस्परिक आरोप प्रत्यारोप, और मीडिया हलचल के बीच अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। बिल्ली की तरह योगी-मोदी के मध्य संबंधों के ख़राब होने का छींका टूटने की आस में बैठे विरोधी अति उत्साह में घूमने लगे, बड़े-बड़े बयान देने लगे।

इस पूरी मीडिया हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शांत भाव से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने काम में लगे हैं, प्रदेश के विकास को गति देने के लिए, जनता की जनसमस्याओं को हल करने के लिए और साथ ही पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए निरंतर स्वयं ही धरातल पर उतरकर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंडल व जिला अध्यक्षों तथा विधायकों से मिलकर पराजय की गहन समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें वह पूछ रहे हैं कि 2019 और 2022 में हमारी विजय का आधार क्या था और 2027 में पीछे रहने का क्या कारण है ? कार्यक्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदा की तरह पूरी कर्मठता से सक्रिय हैं। हाथरस की भीषण दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस में थे और बाढ़ क्षेत्रों में नाव से सर्वेक्षण करते हुए पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं।

कई अफवाहों की धुंध के बीच लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का आयोजन किया गया है। कार्यसमिति की इस बैठक से पहले भाजपा के महामंत्री बीएल संतोष ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक कर पराजय के कारणों की गहन समीक्षा करने के साथ ही सभी उपचुनाव जीतने का संकल्प लिया था।

प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की बैठक से स्पष्ट सन्देश दिया गया है कि प्रदेश में आगामी सभी चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। स्वाभाविक है कि इससे आप नेता अरविंद केजरीवाल, सपा मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस और भाजपा के अंदर बैठे कुछ गुटबाज निराश हो गये हैं। पार्टी के बाहर हों या अन्दर योगी विरोधियों को अब इस सपने से बाहर आना होगा कि उत्तर प्रदेश से योगी जी को हटाया जा रहा है। यह बात अलग है कि आने वाले दिनो में यूपी मंत्रिमडल का विस्तार और फेरबदल आदि हो सकता है और वह जो भी होगा वह इंडी गठबंधन की रणनीतियों को ध्यान में रखकर होगा। कुछ सीटों पर पराजय से प्रदेश की भाजपा सरकार व उसका विकास का एजेंडा बैकफुट पर नहीं जाने वाला है। प्रदेश की भाजपा सरकार समग्र विकास के एजेंडे के साथ हिन्दुत्व के मुद्दे पर भी मजबूती से आगे बढ़ेगी।

प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने संबोधित किया और विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। भाजपा कार्यसमिति की बैठक में राजनैतिक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें एससी व ओबीसी आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई । भाजपा की डबल इंजन सरकार ने एससी व ओबीसी के लिए जो कार्य किये हैं उनके विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रस्ताव में संविधान पर भी चर्चा की गई और कहा गया है कि हमारी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। हम संविधान को सिर्फ राजकाज का हिस्सा नहीं मानते संविधान जनचेतना का हिस्सा हो इसी ध्येय के साथ हमारी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारम्भ किया है। कार्यसमिति में भाजपा को अपेक्षित सफलता न मिल पाने का एक कारण विपक्ष का झूठा प्रचार भी बताया गया है।

भाजपा के प्रस्ताव में सपा पर निशाना साधा गया और कहा गया कि विपक्ष में होने पर पिछड़े दलितों वंचितो के हितैषी होने का ढोंग करने वाले सपाई जब सत्ता में होते हैं तब असली रंग दिखाते हैं। सत्ता में रहते हुए प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने का कार्य करते हैं। भाजपा कार्यसमिति में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान की कड़ी निंदा की गई और कहा गया कि राहुल के बयान से हिंदू समाज आहत है जिसके लिए उन्हें हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। एक अन्य प्रस्ताव में प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की गई।

कार्यसमिति की बैठक में भाजपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पहले सभी 10 उपचुनाव जीतने का संकल्प लिया साथ ही 2027 में प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अभी से जुट जाने की अपील की गई। कार्यसमिति की बैठक में भाजपा ने तीन माह के कार्यक्रम भी घोषित कर दिये गये हैं। समिति की बैठक से यह साफ संदेश जा रहा है कि अब भाजपा दलितों को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।

कार्यसमिति की बैठक में संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान कर उसका विस्तार करने पर बल दिया गया है जिसके लिए अब बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।सदस्यता अभियान भी तीव्र गति से चलाया जाएगा। साथ ही कुछ अन्य कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई है। कार्यसमिति ने विकसित भारत के मंत्र के साथ, कार्यकर्ता प्रथम के विचार के साथ आगे बढ़ने व सभी उपचुनाव जीतने का संकल्प लिया है। कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया में सक्रिय रहने की अपील की गई है। बैठक में सभी नेता इस बात पर सहमत रहे कि कार्यकर्ताओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि अब उछलकूद करने वालों को अवसर नहीं मिलेगा और सभी 10 उपचुनाव बीजेपी ही जीतेगी। यह भी साफ हो गया है कि भाजपा कार्यकर्ता को अब बैकफुट पर नहीं जाना है बीजेपी का नेतृत्व अब फ्रंटफुट पर विपक्ष का मुकाबला करने के लिए मैदान पर उतरने जा रहा है। कार्यसमिति में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हिन्दुत्व की अपनी राह पर चलते रहेंगे।

मुहर्रम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब मुहर्रम पर सड़कें सूनी हो जाती थीं, ताजिया के नाम पर घर तोड़ जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाये जाते थे। आज हमारा स्पष्ट निर्देश है कि पर्व और त्यौहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाओ वरना घर में बैठ जाओ। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है उन्होंने साफ कहा कि जब तक भारत में भगवान राम, कृष्ण और शिवजी की पूजा होती रहेगी तब तक भारत व सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता।

कार्यसमिति ने भी यह बात मान ली है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी पार्टी को भारी पड़ी है इसलिये अब सरकार व संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रमुखता देने की बात हो रही है। कार्यकर्ताओं से संवाद व सामंजस्य बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। भाजपा कार्यसमिति कार्यकर्ताओं के मध्य उपजे भ्रम व संदेह को दूर करने में कितना सफल हो पायेगी यह तो आने वाला समय बतायेगा किंतु अब मुख्यमंत्री पद को लेकर जो संशय व आगामी रणनीति को लेकर जो संदेह था वह अब दूर हो जाना चाहिये क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे और सरकार व संगठन हिन्दुत्व तथा सनातन की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे इसमें कोई संशय या संदेह नहीं रह गया है ।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

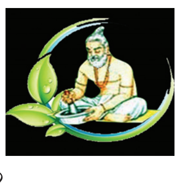

उप-पुराण (भाग-6)

गतांक से आगे...

कवि समय- ख्याति का यह सिद्धान्त है कि ग्रन्थ का नाम उसके निर्माण करने वाले वक्ता के नाम पर तथा उसके प्रतिपाद्य विषय के नाम पर भी हो सकता है यथा- सो प्रतिपाद्य विषय के अनुसार इसे ब्रह्माण्ड-पुराण कहते हैं, और वक्ता के नामानुसार इसे ही वायु-पुराण भी कहते हैं। इसकी वायु-प्रोक्तता के विषय में नीचे लिखा प्रमाण द्रष्टव्य है, यथा: - (सूत जी ने शौनकादि ऋषियों के प्रति कहा) मैं वायु द्वारा कथन किये हुए ब्रह्माण्ड पुराण को तुम्हारे प्रति कहता हूं। उपलब्ध ब्रह्माण्ड-पुराण की अध्याय समाप्ति में भी वायुप्रोक्तसंहितायां ऐसा उल्लेख मिलता है। ऐशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित ब्रह्माण्ड पुराण का मूल नाम ही वायु पुराण छपा हुआ है। कूर्मपुराणोक्त (1।13-15) पुराण गणना में भी ब्रह्माण्ड पुराण के स्थान में अन्तिम पुराण को वायुपुराण के नाम से गिना है।

वायु से शिव या ब्रह्माण्ड ?

अब यह जिज्ञासा हो सकती है कि जब शिव और ब्रह्माण्ड दोनों ही पुराणों की वायु संज्ञा है, फिर गणना में वायु नाम से कहां कौन-सा पुराण ग्राह्य है इसका विवेक कैसा किया जाये ? इस समस्या को हल करने का सरल उपाय यह है कि जिस गणना में शिवपुराण का नाम रहते हुए वायु नाम से अन्य किसी पुराण को गिना हो वहां वायु शब्द से ब्रह्माण्डपुराण समझना चाहिए। इसी प्रकार जिस गणना में ब्रह्माण्ड पुराण% का नाम रहते हुए भी वायु नाम से एक पुराण को याद किया हो वहां उसका अर्थ शिवपुराण समझना चाहिये। जहां पर दो वार वायु नाम से ही दोनों पुराणों को स्मरण किया हो वहाँ पहिले नाम से शिवपुराण को और दूसरे नाम से ब्रह्माण्डपुराण को जानना चाहिए । अभी तक ऐसी गणना हमारी दृष्टि में नहीं पड़ी तथापि सम्भवता में इस नियम का उपयोग हो सकता है। **(क्रमशः)**

विश्व शतरंज दिवस

विकास

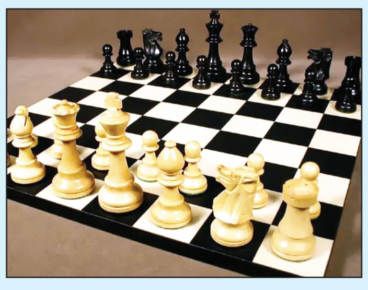

विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन हम किसी को सिखाकर या खेल खेलना सीखकर दिन का पालन कर सकते हैं। शतरंज के खेल में दिमाग की बहुत ज्यादा कसरत हो जाती है इस वजह से इसे 'माइंड गेम' भी कहा जाता है। बता दें शतरंज खेलने से आपके सोचने की क्षमता भी बढ़ती है।

शतरंज सबसे पुराने खेलों में से एक है तथा यह एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है जो विश्व स्तर पर खेला जाता है। शतरंज रणनीति, रणनीति के साथ-साथ दृश्य स्मृति जैसे कौशल विकसित करने में सहायता करता है। यह दिवस विश्वनाथन आनंद, रमेशबाबू प्रज्ञानानंद, मैग्नस कार्लसन जैसे शतरंज खिलाड़ियों पर ध्यान देता है तथा समाज पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

शतरंज वस्तुतः बुद्धिजीवियों का खेल है, जिसमें उच्च-स्तरीय सोच, तत्काल निर्णय लेने दक्षता, कुशलता और बेहतर रणनीत शामिल है। प्रारंभ में यह खेल राजघरानों में खेला जाता था। इस खेल में विचार-मंथन, रचनात्मकता, सामरिक चाल और उच्च-स्तरीय तर्क-वितर्क जरूरी है। शतरंज खेलने से खिलाड़ियों की मानसिक क्षमता बढ़ती है और उन्हें लीक से हटकर सोचने में मदद मिलती है। शतरंज प्रतियोगिता के विजेताओं को अक्सर उच्च मानसिक क्षमताओं वाले शख्सियत के रूप में लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है, शतरंज का खेल व्यक्ति के बौद्धिक विकास एवं सशक्त मानसिक शक्ति के स्तर को दर्शाता है।

12 दिसंबर 2019 को, महासभा ने 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की तारीख को चिह्नित करने के लिए 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में घोषित किया। ऐसा माना जाता है कि शतरंज का खेल, जिसे कभी चतुरंगा के नाम से जाना जाता था, लगभग 1500 साल पहले का है और इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। बाद में इसने फारस में अपना रास्ता बना लिया, जहां यह अरब शासन के तहत फला-फूला और अंततः दक्षिणी यूरोप में फैल गया। यूरोप में, शतरंज अपने वर्तमान स्वरूप में 15वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ। 15वीं सदी के अंत तक यह एक आधुनिक खेल में बदल गया।

शतरंज का पुराना नाम चतुरंग था। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है चारों सेनाएँ। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के अवसर पर, दुनिया भर में कई कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। स्कूल, शतरंज क्लब और सामुदायिक केंद्र शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। यह दिन शतरंज के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इस अद्भुत खेल को सीखने और खेलने के लिए प्रोत्साहित करने का एक शानदार अवसर है।

रिजॉल्व तिब्बत एक्ट के कूटनीतिक मायने

कमलेश पांडे

दुनिया के थानेदार अमेरिका ने तिब्बत के मसले पर चीन को जो दो टूक संदेश दिया है, उससे एक बार फिर वह बौखला उठा है और अमेरिकी नेतृत्व के प्रति अपनी आंखें तरेरनी शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने तिब्बत-चीन विवाद के समाधान को बढ़ावा देने वाले रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जिसमें तिब्बत पर चीन के जारी अवैध कब्जे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दलाईलामा या उनके प्रतिनिधियों के साथ बिना शर्त सीधी बातचीत की बात कही गई है।

हालांकि, चीन ने इस एक्ट का विरोध करते हुए इसे अस्थिरता पैदा करने वाला बताया। उसने इस बिल पर अमेरिका से कड़ा विरोध जताया और साफ शब्दों में कहा कि यह चीन के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप है। कोई भी व्यक्ति या ताकत, जो चीन को नियंत्रित करने के लिए या दबाने के लिए जिजांग (तिब्बत का चीनी नाम) को अस्थिर करने का प्रयास करेगी, सफल नहीं होगी। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा व विकास हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा।

वहीं, इससे उलट निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री सिक्योंग पेम्पा सेरिंग ने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का आभार जताते हुए कहा कि यह कानून तिब्बती लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की बात करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में है। यह चीन के इस प्रचार व दावे को मंजूर नहीं करता कि तिब्बत कभी चीन का हिस्सा रहा है। यह धर्मगुरु दलाईलामा के आशीर्वाद से हो रहा है।

बता दें कि 1950 के दशक में चीन ने भारत की मूक सहमति पर जब तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया तो वहां के सर्वोच्च धर्मगुरु यानी चौदहवें दलाईलामा 1959 में तिब्बत से भागकर भारत चले आये थे, जहां उन्होंने भारत सरकार से शरण मांगी और मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अपनी निर्वासित सरकार स्थापित की। तभी से दलाईलामा से ज्यादा भारत चीन की आंखों में खटक रहा है। भारतीय प्रयासों के बाद 2002 से 2010 तक दलाई लामा के प्रतिनिधियों और चीनी सरकार के बीच नौ दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

अलबत्ता, भारत इस मुद्दे पर भले ही शांत रहा, लेकिन उसके नए मित्र अमेरिका ने उसके दर्द को समझा और एशिया में अपनी राजनीति चमकाने और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर कब्जा जमाने की गरज से चीन के विरोध के बीच रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को अमल में ला दिया। इससे पहले जम्मू-कश्मीर पर उसकी भूमिका से लगभग सभी वाकिफ हैं। इसलिए तो उसे दुनिया का थानेदार कहा जाता है। यह कटु सत्य है कि जिस काम को भारत और रूस को करना चाहिए, उसे करने का श्रेय भी अमेरिका ले चुका है।

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गत 12 जुलाई 2024 को तिब्बत सम्बन्धी विधेयक रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद यह कानून बन गया है। यह प्रस्ताव तिब्बत के लिए अमेरिकी समर्थन बढ़ाने और इस हिमालयी क्षेत्र के दर्जे व शासन से सम्बन्धित विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन और तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाईलामा के बीच संवाद को बढ़ावा देने वाला है। बकौल बाइडन, मैंने एस.138, तिब्बत-चीन विवाद समाधान को बढ़ावा देने वाला अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं तिब्बतियों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी विशिष्ट भाषाई, सांस्कृतिक व धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए संसद के दोनों सदनों की प्रतिबद्धता को साझा करता हूँ। मेरा प्रशासन चीन से दलाईलामा या उनके प्रतिनिधियों के साथ बिना किसी शर्त के सीधी बातचीत शुरू करने का आह्वान करता रहेगा, ताकि मतभेद दूर किये जा सकें और तिब्बत पर बातचीत के जरिए समझौता किया जा सके।

रिजॉल्व तिब्बत एक्ट में कहा गया है कि चीन की नीतियां तिब्बत के लोगों की जीवनशैली को संरक्षित करने की क्षमता को दबाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए यह कानून चीन के इस दावे को खारिज करता है कि तिब्बत प्राचीन काल से उसका हिस्सा रहा है। इस एक्ट में चीन से तिब्बत के इतिहास के बारे में गलत व भ्रामक प्रचार बन्द करने की मांग की है। यह कानून चीन के भ्रामक दावों से निपटने के लिए अमेरिका के विदेश विभाग को भी नए अधिकार देता है।

स्पष्ट है कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का नहीं, बल्कि भारत का पड़ोसी रहते हुए कभी कभार उसका अभिन्न अंग भी रहा है। पहले भारत के डाक वहां जाते थे और भारतीय मुद्रा भी वहां चलती थी। यह बात अलग है कि जब जब भारत के शासक कमजोर हुए तो तब तब वह स्वायत्त या स्वतंत्र देश बन गया। हालांकि आजादी के बाद पंचशील के सिद्धांतों का गला घोंटते हुए चीन ने साल 1959 में जिस तरह से तिब्बत को जबरन अपने भूभाग में मिला लिया और तत्कालीन भारतीय नेतृत्व हिंदी-चीनी भाई-भाई के गफलत में रहकर उसकी इस ओछी कार्रवाई का विरोध तक नहीं किया, वह एक अदूरदर्शी कदम साबित हुआ और उसकी कीमत आजतक भारत चुका रहा है।

अलबत्ता, अमेरिका के नए पैंतरे से साफ है कि अंदरखाने में उसने भारत का विश्वास जरूर हासिल किया होगा। क्योंकि चीन जिस तरह से भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकते हुए उसे दक्षिणी तिब्बत का भूभाग करार देता है, उसके परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी कानून ने यह साफ कर दिया है कि जब तिब्बत ही चीन का हिस्सा नहीं है तो फिर भारतीय भूभाग पर उसका दावा वाकई फर्जी है।

वहीं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीनी हरकतें भी स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं। नेपाल से लेकर भूटान की सीमा तक जो उसकी हरकतें हैं, उसके मद्देनजर रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को चीनी चालों पर एक करारा तमाचा भी समझा जा सकता है, जो भारत ने अपने नए और रणनीतिक दोस्त से दिलवाई है। अब भी यदि चीन नहीं चेतेगा तो तिब्बत का उसके हाथ से फिसलना तय है।

अमेरिका ने जिस तरह से रूस को यूक्रेन में उलझाया, उसी तरह से अब वह चीन को तिब्बत में उलझायेगा। क्योंकि ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने से अच्छा है तिब्बत पर घेरना, ताकि दो मोर्चे पर एक साथ उलझने की गलती वह कर बैठे। अब भारत को भी चाहिए कि चीनी विश्वासघात का बदला ले और तिब्बत मुक्ति संग्राम को शह प्रदान करके अपने ऐतिहासिक भूल को सुधारे, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में भारत के खिलाफ चीन भी तो पाकिस्तान के साथ मिलकर वही कुटिल चाल चलता आया है। इसलिए जैसे को तैसा की तर्ज पर भारत को अमेरिका के साथ मिलकर चीन को कड़ा जवाब जरूर देना चाहिए।

आज का इतिहास

1956 फ्रांस ने ट्यूनीशिया को स्वतंत्र देश घोषित किया।

1963 17 अफ्रीकी देशों और मदगास्कर ने यूरोपियन परिषद् के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये।

1969 अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल ट्रान्यक्विटी के समुद्र पर उतरा, जहां नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन छह-डेढ़ घंटे बाद थीमून पर चलने वाले पहले पुरुष बने।

1969 अमेरिकी खगोलशास्त्री नील आर्म्सट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने।

1982 अनंतिम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों ने लंदन के हाइड पार्क और रीजेंट पार्क में टूबोबोम्स विस्फोट किया, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि ग्यारह अन्य घायल हो गए।

1992 चेकोस्लोवाक के अध्यक्ष वैक्लाव हैवेल ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि हेवल्ड देश के गोलमाल की अध्यक्षता नहीं करेंगे।

1993 वर्जीनिया में व्हाइट हाउस के उप सलाहकार विन्स फोस्टर ने आत्महत्या की।

1997 126 वां ब्रिटिश गोल्फ ओपन- बिली रे ब्राउन ने रॉयल ट्रॉन पर 271 रन बनाए।

1999 चीनी सरकार ने फालुन गोंग के खिलाफ उत्पीड़न अभियान शुरू किया, जिसमें हजारों देशवासी गिरफ्तार हुए।

2001 लंदन स्टॉक एक्सचेंज सार्वजनिक किया गया।

2001 तेईस वर्षीय इतालवी विरोधी वैश्विक कार्लो गिउलिआनी ने 27 वें जी8 शिखर सम्मेलन जेनोवा, इटली के दौरान विरोध प्रदर्शन करते हुए एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी।

2005 कनाडा समान सेक्स विवाह की अनुमति देने वाला 4 वां देश बन गया।

2005 सिविल मैरिज एक्ट ने अपने रॉयल असेंट, कनाडा में वैध-विवाह-सेक्स विवाह प्राप्त किया।

2005 कनाडा में समलैंगिक विवाह को कानूनी स्वीकृति दी गयी और वह ऐसा करने वाला चौथा देश बना।

2010 अमेरिकी विदेश सचिव विलियम हेग का कहना है कि ब्रिटिश सैनिकों को 2014 तक अफगानिस्तान से बाहर होना चाहिए।

2011 गिन्नी में, सैनिकों सहित 80 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जो राष्ट्रपति अल्फा कोनडे पर हत्या के एक असफल प्रयास के लिए गिरफ्तार किए जाते हैं, जो 19 जुलाई को हुआ था।

योगी से कौन छीनना चाहता है यूपी की सत्ता

अभिनय आकाश

बीजेपी के अंदर काफी तनाव है। प्रधानमंत्री जी अमित शाह को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। बाकी लोग ये नहीं चाहते हैं। बीजेपी वालों ने खंडन नहीं किया है कि योगी जी को हटाया जा रहा है। ये बात दबी जुबान में पूरे देश में चल रही है। अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। ये 2 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। चुनाव प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 11 मई को 21 मिनट की स्पीच में ऐसे-ऐसे दावे किए, जिसके काउंटर के लिए खुद देश के गृह मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैदान में उतरना पड़ा। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के पीएम का सवाल उठाकर उस फेस वैल्यू के नैरेटिव को पलटने की कोशिश की, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को लगातार रक्षात्मक मुद्रा में बनाए हुए था। इसके साथ ही आप संयोजक मोदी के कथित उत्तराधिकारियों-अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच दरार पैदा करने की कोशिश के तहत इस बहस को हवा देने की चाल चली। दोनों ही नेताों को अलग-अलग कारणों से अलग-अलग वर्गों की तरफ से स्पष्ट उत्तराधिकारी माना जाता है। एक वक्त था जब पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को देखा जाने लगा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की सत्ता संभाली है। सख्त शासन के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तब से देश की जनता योगी आदित्यनाथ को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखने लगी है। र कैंपेनर के लिहाज से देखें तो उन्हें भाजपा नेताओं में मोदी के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता है। बीजेपी हलकों में दोनों के बीच के आपसी रिश्तों को लेकर संशय जताई जाती रही है। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति ने दिल्ली का पारा भी बढ़ा कर रख दिया है। कोई कह रहा है कि आत्मविश्वास से हारे, लेकिन सवाल किसके आत्मविश्वास से हारे? कोई कह रहा है कि सरकार संगठन से बड़ा नहीं होता, कौन सी सरकार है जो संगठन से बड़ी हो गई है? कोई कह रहा कि अधिकारी काम नहीं कर रहे, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा, किन कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है? कोई कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास पर ठीकरा फोड़ रहा है। कोई संगठन और सरकार के बीच की लकीर खींच दे रहा है। बयान कई हैं, लेकिन इसके मायने क्या है? कुल मिलाकर कहें तो अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया था उसके ईर्द-गिर्द सुर्खियां बुनी गई उसे लेकर लिए अंदरखाने बातचीत अब भी चल रही है। सरकार और संगठन के बीच क्या सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक-एक करके तमाम सवालों का एमआरआई स्कैन करते हैं।

साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की तो इसका श्रेय मोदी शाह की जोड़ी को गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की

80 में से 62 सीटों पर भगवा लहराया तो इसके मैन ऑफ द मैच यही दोनों जोड़ी रही। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 33 सीटें गई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यूपी की राजनीति में लेकिन इससे उलट एक अलग ही खेल चल रहा है। जब से यूपी में बीजेपी की सीटें घटी तब से ऐसा लग रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इस हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ समर्थकों का कहना है कि चुनाव दिल्ली ने अपने हिसाब से लड़ा था। चुनाव के क्रम में योगी आदित्यनाथ की बात नहीं सुनी गई। टिकटों को भी नहीं बदला गया। वैसे ये कोई नया नहीं है कि योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली तक सुर्खियों में न बने रहे हो। सत्ता संभालने के बाद से ही इस बात की चर्चा हमेशा से होती रही कि केंद्र और यूपी की बागडोर संभालने वाले योगी में सब ठीक नहीं है और उन्हें सत्ता से हटाया जा सकता है।

लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपनों के वार बढ़ गए हैं। भाजपा और एनडीए के सहयोगी दल सवाल उठा रहे हैं। एक दिन पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में लखनऊ में परिणाम की समीक्षा हुई और नेताओं को अनुशासन के साथ एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया था। भाजपा एमएलसी देवेंद्र सिंह का सीएम योगी को लिखा पत्र सामने आया है। सिंह ने पत्र में लिखा है, क्या कारण है जनता सरकार से नाराज हो गई? सरकार की छवि शिक्षक-कर्मचारी विरोधी बन गई है। नौकरशाहों के फैसलों से जनाक्रोश है। कोरोनाकाल में 1,621 शिक्षक काल के गाल में समा गए। अब शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। यह ठीक नहीं है। सिंह ने आरोप लगाया कि अफसरों ने मोबाइल खरीदी में जमकर भ्रष्टाचार किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। देवेंद्र सिंह ने लिखा, नौकरशाहों की साजिश से आपको (सीएम को) बचना होगा। गौरतलब है कि भाजपा विधायक रमेशचंद्र मिश्र, एमएलसी बाबूलाल तिवारी व पूर्व मंत्री मोती सिंह भी ऐसे सवाल उठा चुके हैं।

एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा- कुछ 2-4% अधिकारियों जो अंदर से हाथी, साइकिल, पंजा हैं और ऊपर से कमल हैं, ऐसे लोग जो उन पार्टियों से प्रेरित हैं, उनके वजह से नुकसान हो रहा है। अगर किसी गरीब के घर पर बुलडोजर चला देंगे तब तो वह हमें राजनीति में उजाड़ेंगा ही... बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है।

साल 2017 का वो दौर जब यूपी में नरेंद्र मोदी के नाम पर सवार बीजेपी की पतवार ने पूरे दम-खम से जीत सुनिश्चित की और 312 सीटें जीती। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद गाजीपुर से सांसद रहे मनोज सिन्हा का नाम अचानक से सुर्खियों में आ गया और उनकी बायोग्राफी भी मीडिया में तैयार होने लगी साथ ही समीकरण भी पेश किए जाने लगे। मनोज सिन्हा दिल्ली से काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे और वहीं चार्टेड प्लेन का इंतजार करने लगे। दिल्ली में मौजूद केशव मौर्या के चेहरे की मुस्कान इस वक्त और खिलखिला उठी जब लखनऊ के एयरपोर्ट पर नारे लगे पूरा यूपी डोला था, केशव-केशव बोला था। लेकिन तमाम तैरते नामों के बीच योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को यूपी की बागडोर संभाली। 2022 में तो योगी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा और जीता गया। लेकिन 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम की रेस में थे। लेकिन अचानक से सीएम योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। उन्हें डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा था। बताया जाता है कि वही से दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। फिर 2022 में बीजेपी तो जीत गई लेकिन केशव अपनी सीट हार बैठे। उन्हें हारने के बावजूद डेप्युटी सीएम बनाया गया।

धर्म से बड़ी कोई राजनीति नहीं और राजनीति से बड़ा कोई धर्म नहीं। यूं तो ये बात लोहिया ने कही और लोहिया का नाम जपकर समाजवाद के नाम पर सत्ता चलाने वालों को जब यूपी के जनादेश ने मटियामेट कर दिया तो पहली बार किसी धार्मिक स्थल का प्रमुख किसी राज्य का सीएम बना। केंद्र में बीजेपी नेताओं की जिस तरह से स्थिति दिख रही है। यूपी में जिस तरह बीजेपी के संगठन और विधायकों की लामबंदी देखी जा रही है। उससे ये हो सकता है कि योगी को मनाकर केंद्र में कोई मंत्रालय दिया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व की बात करें तो वो इसती आसानी से मानने वालों में नहीं हैं। वो आखिरी दम तक लड़ने में विश्वास रखते हैं और अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। गौरतलब है कि ऐसा भी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के सामने ऐसी चुनौतियां पहली दफा सामने आई है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भी उनकी मुश्किलें बढ़ी थी। लेकिन नवंबर 2021 में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के साथ दो ऐसी तस्वीरें शेयर की जो बताने के लिए पर्याप्त थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं और उनके नेतृत्व को लेकर आलाकमान में कोई संशय नहीं है। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और उनके साथ कुछ चर्चा करते नजर आ रहे थे। उस वक्त पीएम मोदी और अमित शाह से मिल कर योगी ने मार्गदर्शन लिया और समास्या से पार पा लिया। लेकिन क्या बार-बार ऐसा संभव है?

अखिलेश के मानसून ऑफर से दोहरा चरित्र उजागर

उत्तर प्रदेश भाजपा में चल रही आपसी खींचतान के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सोशल मीडिया मंच एक्स पर किये गये ट्वीट से सनसनी फैला दी। उन्होंने लिखा- मानसून ऑफर, सौ लाओ, सरकार बनाओ। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव का स्पष्ट इशारा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ था। अखिलेश 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को सार्वजनिक रूप से यह प्रस्ताव दे चुके थे कि सौ विधायक लाओ, हम समर्थन करके आपकी सरकार बनवा देंगे। एक तरह से उन्होंने फिर से वही प्रस्ताव मौर्य के समक्ष दोहरा दिया है। यहां यह आश्चर्यजनक है कि जब अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक या सांसद पाला बदलते हैं तो वह इसे लोकतंत्र की हत्या और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बताते हैं लेकिन दूसरी ओर वह खुलेआम दूसरे दल में तोड़फोड़ के लिए नेताओं को ऑफर दे रहे हैं। अखिलेश यादव एक ओर संविधान की प्रति दिखा कर उसका पालन करने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों का मखौल उड़ाते हैं। देखा जाये तो आज की राजनीति में नेताओं का दोहरा चरित्र इसे ही कहते हैं। जहां तक केशव प्रसाद मौर्य की बात है तो आपको बता दें कि मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान उन्हें सख्त हिदायत दी गयी कि सोशल मीडिया पर अनाप शनाप टिप्पणियां नहीं करें और पार्टी में एकजुटता बनाये रखने में पूरा सहयोग करें। केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को लखनऊ लौट आये। उनको उम्मीद है कि जल्द ही उनकी ताजपोशी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद पर कर दी जायेगी। माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ज्यादा समय तक योगी सरकार में बने नहीं रहेंगे। इसके संकेत बुधवार को तब और मिल गये जब 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आगामी उपचुनावों को देखते हुए मंत्रियों को जिम्मेदारी बांटी गयी। खास बात यह थी कि इस बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री यानि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उपस्थित नहीं थे। हम आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होने के कारण चल रहे मंथन एवं समीक्षाओं के दौर तथा संगठन एवं सरकार में बड़ा कौन का मुद्दा गर्माने के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस राज्य में पार्टी के संगठनात्मक मामलों से संबंधित कई मुद्दों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री को हार के कारणों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जीती और हारी, सभी सीटों को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के साथ विस्तृत चर्चा की। देखा जाये तो यह अपने आप में महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री किसी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से इतनी लंबी चर्चा करें। प्रधानमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की यह मुलाकात इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले कम सीटें पाने के बाद भाजपा के भीतर अलग-अलग आवाजें उठ रही हैं।

क्रीमी लेयर की आड़ में आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश

अनिल सिन्हा

नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, जो कभी भी बड़ी बहस छेड़ देता है। अभी यह मुद्दा विवादों में घिरी महाराष्ट्र की एक आईएएस अधिकारी के उस सर्टिफिकेट के कारण चर्चा में आया है, जिसमें उन्हें क्रीमी लेयर से बाहर का बताया गया है। यह लेयर पिछड़े वर्ग के उन लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखने के लिए बनाया गया है, जिनके परिवार की सालाना आमदनी आठ लाख रुपये से ज्यादा है। लेकिन इस महिला अधिकारी का मामला सामने आने से पहले से महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी कोटे के भीतर आरक्षण देने की मांग ने जोर पकड़ रखा है। देश के किसी न किसी हिस्से में आरक्षण का मुद्दा गरमाया ही रहता है।

संविधान सभा में आरक्षण पर हुई बहस का जवाब देते हुए बाबा साहेब आंबेडकर ने साफ किया था कि आरक्षण का प्रावधान करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि यह अवसर की समानता के सिद्धांत का उल्लंघन न करे। उनका तर्क था कि नौकरी की ज्यादा सीटें सभी के लिए खुली रख कर अवसर की समानता का पालन हो सकता है। यही वजह है कि 50% से ज्यादा आरक्षण को न्यायपालिका गैर-संवैधानिक करार देती है। आंबेडकर विशेष अवसर के साथ समान अवसर के सिद्धांत पर साथ-साथ चलने के हिमायती थे। दरअसल, निचले पायदान पर खड़े लोगों को ऊंचे पायदान पर खड़े लोगों के साथ स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना समान अवसर के सिद्धांत को ही ताकत देता है।

हालांकि आरक्षण के खिलाफ तर्क देने वाले आज भी अवसर की समानता के सिद्धांत के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। वे दूसरा सवाल मेरिट का उठाते हैं। पहले आरोप का जवाब संविधान के प्रावधानों से ही मिल जाता है। दूसरे तर्क का उत्तर ढूंढना भी कठिन नहीं है। असल में, मेरिट की बात जाति के आधार पर चले आ रहे सदियों पुराने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ही की जाती है। डोनेशन देकर

पढ़ाई करने वालों की मेरिट को लेकर शायद ही इस तरह का संदेह व्यक्त किया जाता है।

संविधान में आरक्षण का प्रावधान नौकरियों और शिक्षा में उन समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है जो गैर-बराबरी व भेदभाव के कारण इससे दूर रह गए हैं। आरक्षण जन्म आधारित जाति व्यवस्था को अपना आधार बनाता है, लेकिन उसे खत्म करने में अपनी भूमिका भी निभाता है। देश को संचालित करने वाले पदों पर सभी तबकों को प्रतिनिधित्व देने से समाज न केवल अधिक लोकतांत्रिक बनता है, बल्कि समाज में समता का रास्ता भी तैयार होता है।

आरक्षण को लेकर होने वाली बहस में क्रीमी लेयर यानी आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों को आरक्षण की सुविधा से वंचित करने का मुद्दा काफी चर्चा में रहता है। इसी तरह उन परिवारों को आरक्षण की सुविधा नहीं देने की मांग अक्सर होती रहती है जिनकी एक पीढ़ी को यह सुविधा मिल चुकी है। आरक्षण समर्थक बुद्धिजीवियों का बड़ा तबका भी इन प्रावधानों के पक्ष में है। लेकिन ये सवाल वास्तव में जटिल हैं।

आजादी के इतने वर्षों के बाद भी सामाजिक यथार्थ में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। यह कहना मुश्किल है कि पद पाने से सामाजिक प्रतिष्ठा मिल ही जाती है और जाति का बंधन शिथिल ही हो जाता है। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान को मजबूत करने और आरक्षण पा चुके परिवारों को इस सुविधा से वंचित करने की मांग इन तबकों के बीच बन रही गैर-बराबरी को दूर करने के उपाय भर हैं। इसे आरक्षण के विरुद्ध सैद्धांतिक हथियार बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

जिन समूहों की सामाजिक और आर्थिक हैसियत वास्तव में बेहतर हो चुकी है, उन्हें आरक्षण से बाहर करने की बात सैद्धांतिक रूप में सही है। लेकिन इस समीक्षा के लिए जरूरी ईमानदार व्यवस्था नदारद है। भर्ती करने वाले तंत्र को लेकर यह शिकायत लगातार आ रही है कि 'योग्य उम्मीदवार नहीं मिले' कह कर वह पद खाली छोड़ देता है।

बहस का एक अहम पहलू यह भी है कि क्या आरक्षण शिक्षा और बेरोजगारी के सवाल को हल करने में मदद करता है? क्या यह जातिवाद पर निर्णायक चोट करता है? यह वाकई दिलचस्प है कि आरक्षण के समर्थक तथा विरोधी, दोनों ही कभी भी संपूर्ण रोजगार की लड़ाई नहीं लड़ते। इसी तरह सामाजिक न्याय की राजनीति का अर्थ सिर्फ आरक्षण की मांग रह गया है। जाति व्यवस्था तोड़ने के लिए कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है।

आरक्षण और जाति की गोलबंदी आपस में इस तरह गुंथ गई है कि आरक्षण का विरोध करते रहे समूह भी अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उन्हें रोजगार पाने का सबसे आसान रास्ता यही दिखाई देता है। वे यह नहीं देख रहे कि आर्थिक नीतियों के कारण रोजगार के अवसर सिकुड़ गए हैं। संगठित क्षेत्र सात प्रतिशत से भी कम रोजगार देता है। कुल रोजगार में सरकारी रोजगार का प्रतिशत भी तीन से ज्यादा नहीं है। ऐसे में, आरक्षण की मांग को लेकर की जा रही जाति आधारित गोलबंदी से रोजगार तो नहीं मिलेगा, लेकिन सामाजिक विभाजन जरूर बढ़ेगा। जाहिर है, आर्थिक तथा सामाजिक बदलाव के व्यापक आंदोलनों के बगैर आरक्षण अपने लक्ष्य नहीं हासिल कर सकता है।

पुराना हिसाब-किताब भी चुकता करना चाहते हैं मौर्य!

नीरज कुमार दुबे

लोकसभा चुनावों में निराशाजनक परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा में मची उठापटक के बीच उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार शाम दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ लंबी बातचीत की। इस दौरान उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। बैठक के बाद भाजपा मुख्यालय से बाहर निकलते समय केशव प्रसाद मौर्य ने मीडियाकर्मियों के सामने कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने अपने मन की बात खुल कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह दी है। देखा जाये तो यह 48 घंटे से भी कम समय में नड्डा के साथ मौर्य की दूसरी मुलाकात थी इसलिए इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा मौर्य की जिस तरह पार्टी के अन्य केंद्रीय नेताओं से मुलाकातें हो रही हैं उसको देखते हुए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में अटकलों का बाजार गर्म है।

हम आपको याद दिला दें कि रविवार को यूपी भाजपा की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि "संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है।" यह कह कर उन्होंने इशारा किया था कि इस समय यूपी में प्रदेश भाजपा संगठन पर सरकार हावी है जिसके चलते कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। कार्यकारिणी की बैठक में नड्डा ने भी भाग लिया था। उस बैठक के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चुनावी हार के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि पार्टी विपक्षी गठबंधन %इंडिया% के प्रचार अभियान का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सकी। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने निराशाजनक परिणाम की सारी जिम्मेदारी उन पर डालने वालों को जवाब देते हुए ही खराब प्रदर्शन का दोष पूरी पार्टी पर डाल दिया था।

जहां तक मौर्य की नाराजगी की बात है तो हम आपको यह भी बता दें कि उनकी योगी से कभी बनी ही नहीं। भाजपा को जब 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत मिला था उस समय केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश

भाजपा अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी थे लेकिन पार्टी ने उन्हें उपमुख्यमंत्री पद दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया था। उस सरकार के दौरान भी जब-तब मौर्य और योगी के बीच अनबन की खबरें आती रहती थीं। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा आलाकमान ने दोनों के बीच सुलह कराई थी जिसके बाद पहली बार योगी अपने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुँचे थे जबकि दोनों नेताओं का सरकारी आवास बेहद करीब ही है। इसके बाद ऐसा लगा कि सब ठीक हो गया है लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य जब सिराथु से हार गये तो उनके करीबियों ने यही कहा कि उन्हें जानबूझकर हराया गया है। नाराज केशव प्रसाद मौर्य योगी की दूसरी सरकार में कोई पद लेने को राजी नहीं थे लेकिन भाजपा आलाकमान ने उन्हें फिर से उपमुख्यमंत्री बनने के लिए मना लिया लेकिन योगी ने मौर्य के पर कतरते हुए उन्हें उनके पिछले वाले विभाग नहीं दिये। इससे मौर्य के मन में जो टीस पैदा हुई वह लोकसभा चुनावों में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद फिर बाहर आ गयी है।

केशव प्रसाद मौर्य जानते हैं कि यही सबसे अच्छा मौका है जब पुराना सारा हिसाब किताब चुकता किया जा सकता है, इसलिए वह समझौते के मूड़ में नहीं बल्कि अपने मुद्दों का पूरी तरह हल निकलवाने के मूड़ में हैं। हम आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से खुद को किनारे किये हुए हैं, वह पार्टी की बैठकों में भी नहीं जा रहे थे, सरकारी बैठकों में भी नहीं जा रहे थे और दो बार कैबिनेट की बैठक में भी नहीं गये। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य बार-बार संगठन की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पद मिल जाये। भाजपा आलाकमान भी इस बात को समझ रहा है कि यदि मौर्य को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बना दिया जाये तो संगठन में नई जान आ जायेगी और मुख्यमंत्री भी काबू में रहेंगे। हम आपको बता दें कि अक्सर यह बात सामने आती है कि योगी दिल्ली की बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए उनके विरोधी माने जाने वाले मौर्य को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाने की तैयारी की जा रही है।

वैसे, केशव प्रसाद मौर्य के बयानों के चलते विपक्ष को योगी सरकार पर निशाना साधने का मौका तो मिला ही है साथ ही भाजपा के सहयोगी दलों को भी आंखें दिखाने और अपनी पुरानी मांगें मनवाने के लिए नये सिरे से दबाव बनाने का अवसर प्राप्त हो गया है। भाजपा की इस अंदरूनी उठापटक पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में, उप्र में शासन-प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। अखिलेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। उन्होंने लिखा है कि जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि यूपी भाजपा की समीक्षा बैठक आनंददायक थी। सिंघवी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि प्रदेश भाजपा की अंदरूनी लड़ाई अब जगजाहिर हो चुकी है। उन्होंने लिखा है कि यूपी में अब तीन सीएम हैं जिसमें से दो अपने नाम के आगे से डिप्टी शब्द हटाने के लिए लालायित हैं। उन्होंने लिखा है कि लगता है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने सरकार के मुखिया को गद्दी से हटाने का फैसला कर लिया है।

बंगाल उपचुनाव में हार से भाजपा को सबक

सुहित के सेन

पश्चिम बंगाल विधानसभा की 4 सीटों के लिए हुए उपचुनावों ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि वह तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) के गढ़ में सेंध लगाने के अपने लक्ष्य का पीछा कर रही है। टी.एम.सी. ने सभी सीटें जीतीं। आमतौर पर, परिणामों को गंभीर झटका नहीं माना जाएगा क्योंकि पारंपरिक ज्ञान है कि विधानसभा उपचुनाव सत्ता में पार्टी के पक्ष में होते हैं। समस्या यह है कि यह घरेलू ज्ञान बारीकियों को ध्यान में नहीं रखता है। सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाजपा ने 2021 के विधानसभा चुनावों में 4 में से 3 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। यह क्षेत्र रायगंज, इसी नाम के लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बगदाह, बोनगांव निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा; और राणाघाट दक्षिण, राणाघाट निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा हैं। 2021 में केवल मानिकतला ही टी.एम.सी. के पाले में गया था। 3 सीटों के नुकसान को शायद ही किसी कथित सत्ताधारी कारक से समझाया जा सकता है। अंतर भी काफी बड़ा है जिससे भाजपा को सामान्य नुस्खों से आराम लेने से बचना चाहिए। रायगंज में, टी.एम.सी. के कृष्ण कल्याणी ने 56,000 से अधिक मतों के अंतर से अपनी सीट जीती। उन्होंने 2021 में भाजपा के टिकट पर लगभग 20,000 मतों से उसी सीट पर जीत हासिल की थी। इससे पहले कि वे टी.एम.सी. में शामिल हो गए, अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया और इस साल की शुरूआत में आम चुनाव में रायगंज संसदीय सीट से चुनाव लड़े। वे भाजपा के कार्तिक पाल से लगभग 68,000 वोटों से हार गए। बगदाह में, मैदान में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार, टी.एम.सी. की मधुपर्णा ठाकुर ने 33,000 से अधिक मतों से चुनाव जीता। 2021 में, भाजपा के विश्वजीत दास ने लगभग 10,000 मतों से सीट जीती थी। इस साल की शुरूआत में हुए आम चुनावों में राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने बोंगांव सीट पर लगभग 75,000 मतों से जीत हासिल की। राणाघाट दक्षिण में, टी.एम.सी. के मुकुटमणि अधिकारी ने 39,000 से अधिक मतों से चुनाव जीता। उन्होंने 2021 में भाजपा के टिकट पर लगभग 17,000 वोटों से सीट जीती थी। इससे पहले कि वह टी.एम.सी. में शामिल हो जाते, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और राणाघाट निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें वे भाजपा उम्मीदवार से 1,80,000 से अधिक मतों से हार गए। मानिकतला में सुप्ति पांडे ने अपने भाजपा प्रतिद्वंद्वी कल्याण चौबे को 62,000 से अधिक मतों से हराया। उनके पति साधन पांडे ने 2021 में लगभग 20,000 मतों से सीट जीती थी। हालांकि टी.एम.सी. के सुदीप बंधोपाध्याय ने आम चुनावों में कोलकाता उत्तर सीट 90,000 से अधिक मतों से जीती थी, लेकिन मानिकतला विधानसभा क्षेत्र में अंतर काफी कम हो गया था। जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वह है भाजपा के कब्जे वाले निर्वाचन क्षेत्रों में भारी बदलाव। रायगंज में 70,000 के करीब और राणाघाट दक्षिण में 55,000 के करीब वोटों का फर्क रहा। इस बीच, भाजपा ने आम चुनावों में आरामदायक जीत दर्ज की थी। मानिकतला में, टी.एम.सी. का अंतर 3 गुना हो गया, जिसने आम चुनावों में खराब प्रदर्शन को दर्ज किया। भाजपा के लिए विशेष ड्क्षचता का विषय यह होना चाहिए कि छोड़ी गई तीनों सीटें उन क्षेत्रों में हैं जिन्हें वह अपना गढ़ मानती है। रायगंज उत्तर बंगाल में है जो 2019 के आम चुनावों के बाद से भाजपा के प्रभाव में है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बगदाह और राणाघाट दक्षिण मतुआ क्षेत्र के केंद्र में हैं। भाजपा ने मतुआ समुदाय के वोट को बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, खासकर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से। इस किले में दरार भाजपा के लिए बुरी खबर होगी क्योंकि मतुआ वोट 30 से अधिक विधानसभा सीटों पर चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं।

पहाड़ों की चादर ओढ़े

मेघालय

शिलांग भारत के उत्तर–पूर्वी राज्य मेघालय की राजधानी है। भारत के पूर्वोत्तर में बसा शिलांग हमेशा से पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। इसे भारत के पूरब का स्कॉटलैण्ड भी कहा जाता है। पहाड़ियों पर बसा छोटा और खूबसूरत शहर पहले असम की राजधानी था। असम के विभाजन के बाद मेघालय बना और शिलांग वहां की राजधानी। लगभग 1695 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस शहर में मौसम हमेशा खुशगवार बना रहता है। मानसून के दौरान जब यहां बारिश होती है, तो पूरे शहर की खूबसूरती और निखर जाती है और शिलांग के चारों तरफ के झरने जीवंत हो उठते है।

शिलांग के अधिकांश लोग खासी नामक जनजाति के हैं। इस जनजाति? के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। खासी जनजाति के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इस जनजाति में महिला को घर का मुखिया माना जाता है। जबकि भारत के अधिकांश परिवारों में पुरुष को प्रमुख माना जाता है। इस जनजाति में परिवार की सबसे बड़ी लड़की को जमीन जायदाद की मालकिन बनाया जाता है। यहां मां का उपनाम ही बच्चे अपने नाम के आगे लगाते हैं।

चेरापुंजी भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य मेघालय का एक शहर है। यह शिलांग से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान दुनिया भर में मशहूर है। हाल ही में इसका नाम चेरापूंजी से बदलकर सोहरा रख दिया गया है। वास्तव में स्थानीय लोग इसे सोहरा नाम से ही जानते हैं। यह स्थान दुनियाभर में सर्वाधिक बारिश के लिए जाना जाता है। इसके नजदीक ही नोहकालीकाई झरना है, जिसे पर्यटक जरूर देखने जाते हैं। यहां कई गुफा भी हैं, जिनमें से कुछ कई किलोमीटर लम्बी हैं। चेरापूंजी बांगलादेश सीमा से काफी करीब है, इसलिए यहां से बांगलादेश को भी देखा जा सकता है।

ऐसा नहीं है की जब भी आप को अपनी छुट्टियाँ मज़ेदार बनानी हो आप गोवा या किसी हिल स्टेशन की ओर निकल पड़ें। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी आपको बेहद सुकून और शांति के अहसास का आनंद मिल सकता है । जी हाँ, अगर आप को माइंड रिफ्रेश करना हो और कुछ दिनों के लिए आप भाग दौड़ से दूर स्ट्रेस फ्री मूड में रहना चाहते हैं तो मेघालय से अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती।

मेघालय यानि 'बादलों का घर', जिसका नाम ही इतना ताज़गी भरा हो सोचिये ज़रा वो जगह भी कितनी शानदार होगी। मेघालय में जो रुहानी राहत और मानसिक शांति मिलती है वो तो बस अनमोल ही है। यहाँ की मनोरम वादियाँ देख कोई भी इसकी खूबसूरती का कायल हुए बिना नहीं रह पायेगा। मेघालय की प्राकृतिक सुन्दरता ही है जो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ का वातावरण भी बहुत ही मनमोहक और ताज़गी से भरपूर होता है। बारिश के दिनों में तो वर्षा से भरे बादलों के बीच मेघालय की पहाड़ियां बहुत दिल लुभावनी दिखाई देती हैं।

मेघालय में घूमने के लिए बहुत सी शानदार जगहें हैं जहाँ प्रकृति की असली सुन्दरता बहुत ही भव्य रूप में नज़र आती है।

शीतल शिलॉग

मेघालय का कैपिटल शिलॉग पर्यटकों का सबसे महत्वपूर्ण टूरिज्म डेस्टिनेशन है। और भला ऐसे कैसे हो सकता है कि आप भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जायें और शिलॉग न देखें । शिलॉग जाये बिना तो आपके घूमने का मज़ा अधुरा ही रह जायेगा। शिलॉग की लाजवाब खूबसूरती और यहाँ की ऊँची-ऊँची पहाड़ियां आप का दिल चुरा लेंगी। शिलॉग जाने के लिए बारिश का मौसम बहुत ही उत्तम होता है। शिलॉग की किसी पर्वत चोटी पर खड़े हो कर पूरे शहर का अद्वितीय नज़ारा लिया जा सकता है। शिलॉग में अनेक मनोरम स्थल हैं जिन में वार्ड लेक, लेडी हैदरी पार्क, पोलो ग्राउंड और मिनी चिड़ियाघर प्रमुख हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्द है एलीफैंट वाटर फॉल जो बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही यहाँ पर लोग एयर बैलून का भी पूरा लुत्फ़ उठाते हैं।

चंचल चेरापूंजी

चेरापूंजी नाम सुनते ही बचपन में पढ़ा जियोग्राफी का वो चैप्टर याद आ जाता है ना जिसमे हमने पढ़ा था 'चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है'। सोचिये कितना रोमांच भरा होगा ऐसी जगह को हकीकत में देखना । चेरापूंजी पर्यटकों का फेवरेट स्पॉट है। चेरापूंजी में माकडॉक और डिमपेप घाटी का दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। चेरापूंजी की बारिश की बूंदे तन-मन को ऐसे भिगो देंगी की दिल ताज़गी से भर उठेगा। चेरापूंजी का सबसे आकर्षक स्थान है नोहकलिकाई झरना। हजारों फीट ऊपर से गिरता यह दूधिया सफ़ेद झरना बहुत ही मनमोहक और खूबसूरत है। इसके अलावा चेरापूंजी का माउलंग सीम पीक एक ऐसा

स्थान है जो यात्रियों के लिए रहस्य, रोमांच, साहस और सौंदर्य से भरा हुआ है। दूर एक हज़ार मीटर ऊंचाई से गिरता झरना, घने वृक्षों से घिरा जंगल, बादलों के पास बसा बांग्लादेश यहां से दिखाई देता है।

मेघालय में पाई जाने वाली गारो पहाडियों में तो मानसून के मौसम में घूमने का मज़ा दोगुना हो जायेगा। मानसूनी सीजन के वक्त यहाँ बादल हमेशा बने रहते हैं। खासी और जेंतिया पहाड़ी की ऊंचाई पर एक विशेष प्रकार का मौसम रहता है, जिसमें हल्की ठंडक ह्द्भ्ढ्ढह्ल्द्ब है। विंटर में यहां तेज़ सर्दी पड़ती है। इसके साथ ही रामकृष्ण का मंदिर, नोखालीकाई वॉटर फॉल, वेल्श मिशनरियों की दरगाहें, ईको पार्क, डबल ड्रेकर रूट ब्रिज और चेरापूंजी मौसम विभाग वैधशाला देखने लायक स्थान हैं। चेरापूंजी में होने वाली तेज़ बारिश से यहाँ की चट्टानों में दरार पड़ गई है और सभी ढलानों पर झरने का दृश्य बेहद मनोरम है।

मेघालय देश के उत्तरी पूर्व क्षेत्र का खूबसूरत राज्य है जिसे देख कर लगता हैं मानो इसने पहाड़ की चादर ओढ़ रखी हो। इस राज्य का एक तिहाई हिस्सा घने जंगलों से भरा है। इस

राज्य को पूरब का स्काटलैंड कहा जाता है। यहां पूरे देश के मुकाबले बहुत ज्यादा बारिश होती है।

मेघालय बायोडाइवरसिटी यानी जैविक विविधता से भरपूर है। यहां पौधे, जीव-जन्तु और पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। मेघालय में खेती में प्राथमिकता दी गई है। यहां की मुख्य फसलें हैं- केला, मक्का, अनानास, आलू और चावल। मेघालय की शिलांग चोटी को यहां के निवासी भगवान का निवास स्थल मानते हैं।

पर्यटकों का यहां हर समय तांता लगा रहता है। इस राज्य की खूबसूरती और इसके मनमोहक दृश्य के कारण पर्यटक खिंचे चले आते हैं। यहां तीन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और दो नेशनल पार्क हैं। ट्रैकिंग, हाइकिंग और पर्वतारोहण के दीवानों के लिए यह जगह बेहतर है। यहां यूमियान लेक में वॉटर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा सकता है। यहां के लोगों में वॉटर स्पोर्ट्स काफी लोकप्रिय है।

चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बनी लगभग 500 गुफाएं यहां मौजूद हैं। जिनमें से कुछ ऐसी भी हैं, जो देश की सबसे लंबी और गहरी गुफा है। ये गुफाएं देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। इस राज्य का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है चेरापूंजी। यहां के अद्भुत प्राकृतिक दृश्य पूरे उत्तरी-पूर्व भारत में सबसे अनोखे और दर्शनीय हैं।

यहां कई वाटरफॉल हैं। जैसे शेदेथम फॉल्स, विनिया फॉल्स, एलिफेंट फाल्स, नोहकालीलाई, स्वीट फॉल्स, विशप्स फाल्स और लैंगशियांग फॉल्स। इन झरनों की खूबसूरती देखते बनती है। मेघालय को खैसिस, जैंटिया और गैरो हिल्स के अनुसार विभिन्न भागों में बांटा गया है। यहां कई नदियां हैं, जिनमें कुछ मौसमी हैं। इनमें से कुछ नदियां खूबसूरत वाटरफॉल बनाती हैं।

मेघालय घूमने का सबसे अच्छा मौसम है गर्मियां। वैसे आप मेघालय कभी भी जाएं गर्म कपड़ों की जरूरत हमेशा पड़ती है। सड़क, रेल और हवाई यातायात के साथ यहां हेलिकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जो शिलांग से गुवाहाटी को जोड़ती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

2041 तक एक मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा असम: हिमंत

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बार फिर कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी बवाल छिड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि असम में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में लगभग 30 प्रतिशत बढ़ रही है, और वे 2041 तक बहुसंख्यक हो जाएंगे। गुरुवार को गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सांख्यिकीय नमूने के अनुसार मुसलमान अब असम की आबादी का 40 प्रतिशत हो गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। यह एक वास्तविकता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही हिमंता ने कांग्रेस पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एंबेसडर बन जाते हैं, तो यह नियंत्रित हो जाएगा क्योंकि समुदाय केवल उनकी बात सुनता है।

नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकती हैं ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र की मोदी सरकार के बीच रिश्ते बहुत कम ही सहज नजर आया है। ममता लगातार मोदी सरकार की कड़ी आलोचक बनी हुई हैं। साथ ही साथ केंद्र की सरकार पर बंगाल से भेदभाव का भी आरोप लगाती हैं। इन सब के बीच खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकती हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्यों कई मौके पर वह इस बैठक से दूर ही रही हैं। साथ ही साथ इसपर सवाल भी खड़े किए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि ममता के 25 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारी ने कहा कि बैठक में बनर्जी राज्य को केंद्रीय बकाया और ग्रामीण आवास और मनरेगा के लिए धन का मुद्दा उठा सकती हैं।

महाराष्ट्र में कांग्रेस-सपा मिलकर लड़ेंगी विस चुनाव!

नईदिल्ली। देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी अब अपने विस्तार के लिए नए-नए सियासी रास्ते खोजने के लिए आगे बढ़ चली हैं। इस कड़ी में सबसे पहला पड़ाव समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सभी 37 सांसदों का शुक्रवार को स्वागत समारोह होने जा रहा है। स्वागत समारोह के बहाने समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन की मजबूती तलाशने की पूरी तैयारी में है। वहीं सूत्रों की मानें तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन वाले महाविकास अगाढ़ी के साथ मिलकर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले महानगरपालिका के चुनाव में भी शिरकत करने के लिए जमीनी तैयारी में लगी है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद अपने विस्तार के लिए कई बड़ी योजनाएं तैयार की हैं। पार्टी के रणनीतिकारों की मानें, तो इस विस्तार में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर मजबूती के साथ अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी में है।

क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों पर कार्रवाई

मुंबई। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की है। हाल ही में महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में एनडीए के सभी उम्मीदवारों की जीत हुई थी। जबकि कांग्रेस-शिवसेना और शरद पवार वाली एमवीए से तीन में से दो उम्मीदवार ही जीते। चुनाव में एनडीए ने अपनी सभी नौ सीटें जीत लीं। महाविकास अघाड़ी (एमवीए) की तरफ से कांग्रेस की प्रज्ञा सातव और शिवसेना उद्धव गुट के मिलिंद नार्वेकर भी जीत गए। जबकि पीडब्ल्यूपीआई के जयंत पाटिल हार गए। 37 विधायकों वाली कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार प्रद्यना सातव के लिए 30 प्रथम वरीयता वोटों का कोटा तय किया था। जबकि शेष सात वोट सहयोगी पार्टी शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर को मिलने थे। मगर परिणाम में सातव को 25 और नार्वेकर को 22 प्रथम वरीयता वोट मिले। इससे साफ हुआ कि सात कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की।

दिल्ली पहुंचा आंध्र प्रदेश की सियासी लड़ाई

अमरावती। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी वाईएसआरसीपी नेता वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सत्तारूढ़ टीडीपी और उसके सहयोगियों द्वारा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित अत्याचारों की शिकायत की। रेड्डी ने आरोप लगाया कि केवल एक महीने में 31 लोगों की हत्या कर दी गई, 35 लोगों ने आत्महत्या कर ली, 560 निजी और 490 सरकारी संपत्तियां नष्ट कर दी गईं और 2,700 लोगों को अपने गांवों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। रेड्डी ने साझा किए गए पत्र में कहा, इसके अलावा, हिंसा और हमलों की 1,050 से अधिक घटनाएं हुई हैं। यह वर्तमान सरकार के तहत हमारे राज्य में मामलों की स्थिति को दर्शाता है, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। पूर्व सीएम के अनुसार, ये घटनाएं वाईएसआरसीपी को दबाने के लिए एक दुष्ट डिजाइन का हिस्सा थीं, जिसका एकमात्र उद्देश्य पार्टी से जुड़े किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक परिदृश्य से बाहर करना था।

ओडिशा को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे : नड्डा

भुवनेश्वर। ओडिशा भाजपा प्रमुख मनमोहन सामल की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राज्य कार्यकारी समिति की बैठक आज पुरी में शुरू हो गई है। आज बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक बैठक में राज्य के मौजूदा राजनीतिक और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं को नड्डा ने संबोधित भी किया। अपने संबोधन के शुरूआत में उन्होंने कहा कि मैं ओडिशा भाजपा के एक-एक कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। क्योंकि आप सभी ने पूरी ताकत लगाकर ओडिशा में कमल खिलाया है।

नड्डा ने कहा कि हम अपने लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम अनुसूचित जाति समुदाय और हमारे आदिवासी भाइयों को मुख्यधारा में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ओडिशा के हमारे आदिवासी भाइयों-बहनों ने भी भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया है। आज हमारे 18 विधायक ट्राइबल समाज से हैं। इसलिए मैं आदिवासी भाइयों-बहनों का धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक प्रजातंत्र है, भाई-भतीजावाद नहीं है, अपना-पराया नहीं है। बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक %परजीवी% बन गई है, जो अपना पेट भरने के लिए दूसरों की ताकत का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खोखले वादों के अलावा किसी और चीज़ पर भरोसा नहीं करती है, और %बैसाखी% के अलावा किसी और चीज़ पर नहीं चलती है।

अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद के बल पर खड़ी नहीं हो सकती है, ये बैसाखियों पर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को संविधान से कोई लेना-देना नहीं है। ये संविधान के रक्षक नहीं, बल्कि भक्षक हैं। इन्होंने संविधान को एक बार नहीं, बल्कि अनेकों बार आघात पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को याद कीजिए, इन्होंने रातों-रात हमें जेलखानों में डाल दिया था। 1 लाख 25 हजार लोगों को जेल में डाल दिया था। ये राहुल क्या जानें अपनी दादी के कारनामें। कांग्रेस पार्टी ने 90 बार चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया।

नड्डा ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चल सकता। जिसे मोदी जी की इच्छाशक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशायी कर जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत अनिर्णय, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से त्रस्त था। हालाँकि, प्रधान मंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हमारे देश ने सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मार्गदर्शक सिद्धांतों को अपनाते हुए एक परिवर्तनकारी यात्रा की है। आज, भारत नए उद्देश्य और प्रगति की भावना के साथ चमक रहा है।

मानसून सत्र 22 से, छह नए विधेयक होंगे पेश

वित्त मंत्री सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी

नईदिल्ली। अगले सप्ताह शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक सहित छह नए विधेयक पेश किये जायेंगे। वित्त विधेयक के अलावा, सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कारोबार को सुगम बनाने के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने को लेकर विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करने के वास्ते भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। विधेयकों की सूची बृहस्पतिवार शाम को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी संसद बुलेटिन में प्रकाशित की गई। मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सत्र के दौरान पेश किये जाने और पारित होने के लिए सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता-पूर्व कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) का भी गठन किया। अध्यक्ष के नेतृत्व वाली समिति में सुदीप बंदोपाध्याय (तृणमूल कांग्रेस), पी पी चौधरी (भाजपा), लवू श्रीकृष्ण देवरायलु (तेदेपा), निशिकांत दुबे (भाजपा), गौरव गोगोई (कांग्रेस), संजय जायसवाल (भाजपा), दिलेश्वर कामत (जदयू), भर्तृहरि महताब (भाजपा), दयानिधि मारन (द्रमुक), बैजयंत पांडा (भाजपा), अरविंद सावंत (शिवसेना-यूबीटी), के. सुरेश (कांग्रेस), अनुराग ठाकुर (भाजपा) और लालजी वर्मा (सपा) सदस्य हैं।

अखिलेश के मानसून ऑफर को 2027 में 47 पर लाएंगे: मौर्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में ट्वीट वार जारी है। अखिलेश यादव ने भाजपा में राजनीतिक चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा था है 'मानसून पेशकश है-100 लाओ और सरकार बनाओ।' इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। ट्वीट कर कहा कि मानसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज़ और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य ख़तरे में है। वह मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहरायेंगे, फिर कमल की सरकार बनायेंगे। प्रदेश में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है, भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहरायेगी। फिर डबल इंजन सरकार।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव के मानसून ऑफर के एक दिन बाद शुक्रवार को पलटवार करते हुए कहा कि इसे 2027 में जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर 47 पर समेटेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा में राजनीतिक चर्चाओं के बीच 'एक्स' पर बृहस्पतिवार को कहा था '' मानसून पेशकश है-100 लाओ और सरकार बनाओ।'' मौर्य ने शुक्रवार को एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि मानसून 'ऑफर' को 2027 में जनता और कार्यकर्ता फिर 47 पर समेटेंगे। इसी पोस्ट में उपमुख्यमंत्री ने कहा, एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल, जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वह मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता।

आरएसएस के मुरीद हुए दिग्विजय सिंह!

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दे दी सीखने की नसीहत

भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरएसएस के कट्टर आलोचकों में से एक दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक नसीहत दी है। उन्होंने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखें कि संदेश को प्रभावी ढंग से कैसे संप्रेषित किया जाए और संगठन के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करें। दिग्विजय सिंह ने यह बात जबलपुर में कही जब वे कथित नर्सिंग कॉलेज घोटाले और नीट प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे।

अपने संबोधन में दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ से सीखिए, हालांकि हम उनके कट्टर विरोधी हैं। वे दिमागी खेल खेलते हैं। वे कभी विरोध नहीं करेंगे, कभी प्रदर्शन नहीं करेंगे, कभी पिटेंगे नहीं, कभी जेल नहीं जाएंगे, बल्कि वे हमें जेल भेज देंगे। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस आम तौर पर तीन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है- पर्चे बांटना, चर्चाएं आयोजित करना और अंत में आंदोलन पर होने वाला खर्च। अगर आप उनसे लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें उनके ही खेल में हराएं, बेशक, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि बौद्धिक रूप से।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर संगठनात्मक नेटवर्क के अभाव में विरोध प्रदर्शन प्रभावी साबित नहीं होंगे। उन्होंने बूथ से लेकर जिले तक तीन स्तरों पर आंदोलन करने का सुझाव दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि संघ की कार्यप्रणाली और दुष्प्रचार को समझकर उसका प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकता है। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिंह ने राज्य चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर निराशा व्यक्त की और कहा कि पार्टी फिलहाल इस असफलता के कारणों का विश्लेषण कर रही है।

सिंह ने कहा कि भाजपा ने दावा किया था कि वह लोकसभा चुनावों में 400 सीटें हासिल करेगी, लेकिन वह 250 सीटें भी हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने भाजपा को मिले बहुमत का श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के समर्थन को दिया। इसके अलावा, सिंह ने नीट प्रश्नपत्र लीक कांड के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी की आलोचना की और सवाल किया कि परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, सिंह ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोप भी लगाए।

खेल
प्रमुख समाचार

हार्दिक की जगह सूर्यकुमार यादव को टी20 की कप्तानी

नईदिल्ली। टीम इंडिया के नए हेड कोच बने गौतम गंभीर ने पहली बार अपनी टीम चुन ली है। श्रीलंका के खिलाफ 27 जुलाई से शुरू होने वाली टी20 और फिर वनडे सीरीज के लिए 18 जुलाई की रात टीम इंडिया का ऐलान किया गया। टीम चयन में गौतम गंभीर की छाप दिखी जहां उन्होंने हार्दिक पंड्या को कप्तानी से हटा दिया और सूर्यकुमार को नया कप्तान बनाया। जबकि ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा के संन्यास के बाद हार्दिक को कप्तानी मिलेगी। वनडे कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए खुद को उपलब्ध बताया है।

गौतम गंभीर का सूर्यकुमार यादव पर विश्वास जताना कोई भी नई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चिंता वाली बात ये है कि हार्दिक पंड्या को किसी भी तरह के लीडरशिप रोल से बाहर कर दिया गया है। टी20 वर्ल्ड चैंपियन टीम के उपकप्तान रहे पंड्या को हटाकर अब सफेद गेंद के दोनों फॉर्मेट में शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। पंड्या चोटिल होने से पहले 2023 में 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी उपकप्तान थे। वहीं शुभमन गिल को दोनों प्रारूपों में उपकप्तान नियुक्त किए जाने के साथ अब ये साफ हो गया है कि चयन समिति और खास तौर पर गंभीर से गिल को सभी फॉर्मेट में भारत के अगले कप्तान के रूप में तैयार करना चाहते हैं।

टी20 वर्ल्ड कप में जो शुभमन गिल स्क्वॉड का हिस्सा तक नहीं थे, उन्हें अचानक टीम का उपकप्तान बना दिया गया। ऐसा लगता है कि गंभीर की नजर 2027 वर्ल्ड कप पर टिकी हुई है। भविष्य के कप्तान के रूप में उनका वोट गिल के साथ है। रोहित के 37 और सूर्यकुमार के 33 साल के होने के कारण गंभीर अभी भी नई लीडरशिप तैयार करना चाहते हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/ प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 739 अंक टूटकर 81 हजार से नीचे आया

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को जारी चार दिनों की रिकॉर्ड तोड़ तेजी पर ब्रेक लग गया। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर रूझानों के बीच बाजार के नए शिखर पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली करना पसंद किया। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 81,587.76 के अपने नए ऑलटाइम हाई पर पहुंच गया, लेकिन बढ़त को आगे जारी रखने में विफल रहा और 738.81 अंक या 0.91 प्रतिशत गिरकर 81,000 अंक से नीचे 80,604.65 पर बंद हुआ। दिन के दौरान यह 844.36 अंक या 1.03 प्रतिशत गिरकर 80,499.10 पर आ गया। यह इंडेक्स गुरुवार को पहली बार 81 हजार के पार निकल गया था। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 269.95 अंक या 1.09 प्रतिशत लुढ़क गया और शुरुआती कारोबार के दौरान 24,854.80 के अपने नए रिकॉर्ड शिखर पर पहुंचने के बाद 24,530.90 पर बंद हुआ।

पेटीएम का घाटा जून तिमाही में बढ़कर 840 करोड़ रु. पर

नईदिल्ली। पेटीएम के ब्रांड नाम से अपना कारोबार चलाने वाली फिन टेक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के घाटे में दोगुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। कंपनी ने शुक्रवार को अपने फाइनेंशियल रिजल्ट का ऐलान करते बताया कि जून तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड घाटा बढ़कर 840 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पेटीएम की रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, इससे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की इसी तिमाही में कंपनी को 358.4 करोड़ रुपये का कुल घाटा हुआ था। इसके अलावा पेटीएम का कंसॉलिडेटिड रेवेन्यू 30 जून को समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 33.48 प्रतिशत घटकर 1,639.1 करोड़ रुपये पर आ गया। एक साल पहले की इसी तिमाही में यह 2,464.2 करोड़ रुपये था। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से पेटीएम पर की गई कार्रवाई का कंपनी के नतीजों में असर देखने को मिला है।

दुनियाभर में विमान सेवाएं हुई प्रभावित, सर्वर में आई खराबी

नईदिल्ली। सर्वर में खराबी से दुनियाभर में विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इस संबंध में स्पाइसेट, इंडिगो जैसी एयरलाइंस कंपनी ने जानकारी साझा की है। स्पाइसजेट ने एक्स पर पोस्ट किया। स्पाइसजेट ने लिखा कि हम वर्तमान में अपने सेवा प्रदाता के साथ तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिससे बुकिंग, चेक-इन और बुकिंग कार्यक्षमताओं सहित ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। परिणामस्वरूप, हमने हवाई अड्डों पर मैन्युअल चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रियाएं सक्रिय कर दी हैं। हम आगामी यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे काउंटरों पर चेक-इन पूरा करने के लिए सामान्य से पहले हवाई अड्डे पर पहुंचें। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हमें ईमानदारी से खेद है और आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारी टीमें इन समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए हमारे सेवा प्रदाता के साथ लगन से काम कर रही हैं।

सरकार के साथ समन्वय से अर्थव्यवस्था में हुआ सुधार

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने शुक्रवार को कहा कि उनके करीब छह साल के कार्यकाल के दौरान सरकार के साथ रिजर्व बैंक के संबंध अच्छे रहे हैं। उन्होंने कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार का श्रेय दोनों के बीच बेहतर समन्वय को दिया। यहां अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस के बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा) सम्मेलन में दास ने कहा कि किसी ने भी उनसे यह उम्मीद नहीं की थी कि वे अपने कार्यकाल के दौरान सरकार के लिए 'चीयरलीडर' बनेंगे। दास ने कहा कि आरबीआई चालू वित्त वर्ष (2024-25) में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान को हासिल करने के लिए पूरी तरह से आशान्वित है। उन्होंने कहा कि वृद्धि दर बेहतर रहने के साथ मौद्रिक नीति का ध्यान पूरी तरह से मुद्रास्फीति को काबू में लाने पर है।''

नया बजट अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए, यही चाहते हैं देशवासी

सतीश सिंह

नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद देशवासियों की विकास के मोर्चे पर और भी बेहतरी आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पिछले दो कार्यकाल में उनकी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, सेवा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए। सबसे कारगर कदम आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र में उठाए गए। 2014 से 2023 के दौरान भारत आर्थिक रूप से विश्व में मजबूत देश बनकर उभरा है।

उम्मीद है कि भारत 2027 में पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, 2030 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 में एक विकसित देश बन सकता है। 1947 से 2007?तक?भारत की जीडीपी?10 खरब डॉलर की हुई और 2014 में बढ़कर 20 खरब डॉलर की हो गई और 2019 में 30 खरब डॉलर की। 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी, जबकि 2019 में यानी सिर्फ पांच वर्षों के अंदर यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई।

वित्त वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही में 7.8 फीसदी की दर से जीडीपी में वृद्धि हुई। समग्र रूप से 2023-24 में विकास दर 8.2 फीसदी रही। 'द इंडियन इकनॉमी: ए रिव्यू' रिपोर्ट के अनुसार, 2024-25 में लगातार चौथे साल भारत की जीडीपी वृद्धि दर सात प्रतिशत से अधिक रह सकती है, जबकि अभी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर करीब तीन फीसदी है। 2023 में भारत में बेरोजगारी दर 8.7 प्रतिशत रही थी। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है, इसलिए 2027 तक बेरोजगारी दर के आठ प्रतिशत से कम रहने का अनुमान है।

भारत में मुद्रास्फीति दर 2023 में 5.5 प्रतिशत रही है, जबकि 2022 में यह 6.7 प्रतिशत रही थी। मई 2024 में खुदरा महंगाई दर 4.75 प्रतिशत रही। वहीं, 2024 से 2027 के दौरान इसके क्रमशः 4.6, 4.1, 4.1 और 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस आधार पर कहा जा सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था आसानी से 2027 तक 50 खरब डॉलर की बन सकती है।

ए रिव्यू' रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के आर्थिक सुधारों की वजह से ही भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकी है। भारत की जीडीपी 2030 तक सात प्रतिशत की दर से आगे बढ़ सकती है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसऐंडपी ग्लोबल ने भी भारत के वित्तीय क्षेत्र में आई मजबूती की पुष्टि की है। एसएंडपी ग्लोबल ने अपनी ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 की रिपोर्ट 'न्यू रिस्क, न्यू प्लेबुक' में कहा कि भारत की नॉमिनल जीडीपी 2022 में 35 खरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 73 खरब डॉलर हो जाएगी। हाल के महीनों में भारतीय बैंकों का प्रदर्शन एशिया में अपने समकक्ष बैंकों की तुलना में सबसे अच्छा रहा है। देश के तीन बड़े बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने 2023 में दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों की सूची में अपनी जगह बनाई है। एसएंडपी ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में बैंकों की संपत्ति 50.50 प्रतिशत बढ़कर 1.51 लाख करोड़ डॉलर हो गई है। एसऐंडपी ग्लोबल के मुताबिक, हाल के महीनों में भारतीय बैंकों द्वारा दिए जा रहे कर्ज में तेज वृद्धि हुई है। 29 दिसंबर, 2023 तक यह 15.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई थी, जो एक साल पहले 14.9 प्रतिशत थी। 31 मार्च, 2024 को सरकारी बैंकों का संचयी लाभ 1.4 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया, जोकि पिछले साल की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। 2023-24 में सभी बैंकों का शुद्ध फंसा कर्ज (एनपीए) भी घटकर 1.70 प्रतिशत के स्तर से भी नीचे आ गया। विकसित देश बनने के कुछ मानक हैं। वित्त मंत्रालय का कामकाज फिर से निर्मला सीतारमण के हाथों में है। इसलिए, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां और उठाए जाने वाले कदम आगामी समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बैंकों के अनुकूल रहेंगे। लिहाजा, देशवासी चाहते हैं कि नया बजट अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए।

सांसद पांडेय का संसद में दिए गए भाषण पर बघेल का प्रलाप खीझ से ज्यादा कुछ नहीं है

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने महादेव एप घोटाले को लेकर लोकसभा में भाजपा सांसद संतोष पांडेय के संबोधन के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य प्रस्तुत करने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष याचिका पेश किए जाने को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोरा राजनीतिक प्रपंच बताया है। श्री शर्मा ने कहा कि सत्ता से बेदखल होने और राजनांदगाँव में करारी हार के बाद कांग्रेस में अलग-थलग पड़ चुके बघेल की नियति ही यही हो गई है कि अखबारी सुर्खियों में खुद को बनाए रखने के लिए वह अब इस तरह का पाखंड रचकर बीच-बीच में रोना-धोना मचाते रहें।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बघेल का लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला के समक्ष याचिका पेश करना केवल सियासी ड्रामा है और इस तरह की ड्रामेबाजी करके झूठ की राजनीति करने के बघेल माहिर खिलाड़ी हैं। भूपेश सरकार के कार्यकाल में इतने घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं कि प्रदेश की जनता कराह उठी थी। डीएमएफ घोटाला, राशन घोटाला, शराब घोटाला, कोल घोटाला, महादेव सट्टा एप घोटाला हुआ। रेत, जमीन, पीएससी, गोबर, गौठान जैसे जाने कितने घोटाले भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुए हैं और तत्कालीन मुख्यमंत्री होने के नाते वह इस प्रकार की सियासी लफ्फाजियाँ करके अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते।

श्री शर्मा ने कहा कि सांसद पांडेय के संसद में दिए गए संबोधन को लेकर प्रलाप कर रहे बघेल में अगर हिम्मत है तो अपनी उपसचिव रही सौम्या चौरसिया के बारे में बोलकर दिखाएँ जो पिछले डेढ़ साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है और जिसकी जमानत याचिका बार-बार खारिज हो रही है। बघेल को इस बात पर लज्जा कब महसूस होगी कि सौम्या द्वारा बार-बार याचिका लगाने पर अदालत ने सौम्या पर जुर्माना तक ठोका है। श्री शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर बघेल की जुबान पर ताला लगा हुआ है। बघेल सौम्या को लेकर चुप क्यों बैठे हुए हैं जबकि मुख्यमंत्री रहते हुए वह सौम्या के वकील बने फिर रहे थे और कह रहे थे कि सौम्या के साथ गलत हो रहा है। बघेल तब यह भी दावा कर रहे थे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि बघेल झूठ का रायता चाहे जितना फैलाएँ, पर सत्य और तथ्य अब सामने आ रहे हैं। शराब घोटाले के आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार कर लिया कि शराब घोटाला हुआ था। जिस भूपेश सरकार के कार्यकाल में इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया, नकली होलोग्राम तक बन गया जो हाल ही ढेबर के खेत को खोदकर निकाला गया है और बघेल के मुँह में दही जमा हुआ है! कोयला घोटाला हो गया, उसके आरोपियों को जमानत नहीं मिल रही है। राशन घोटाला हो गया। श्री शर्मा ने कहा कि इसलिए बघेल को इस बात को स्वीकारना चाहिए कि कांग्रेस के शासनकाल में हुए तमाम घोटालों की जांच की आँच से बचने के लिए इन घोटालों के संरक्षक भूपेश बघेल अब अपनी सफाई देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख रहे हैं, याचिका दे रहे हैं। संसद में दिए गए भाषण पर भूपेश बघेल का यह प्रलाप दरअसल श्री संतोष पांडेय के मुकाबले राजनांदगांव के लोकसभा चुनाव में पटखनी खा चुकने की खीझ से ज्यादा कुछ नहीं है। श्री शर्मा ने कहा कि घोटालेबाज जो हैं, उनके बारे में विषय उठाने बहुत जरूरी हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है। बघेल अब यह बात अच्छी तरह समझ लें कि अब यह ड्रामा चलने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता बघेल की ड्रामेबाजी और पैंतरेबाजी को समझ चुकी है।

विधानसभा मानसून सत्र के लिए एकजुट हुई भाजपा, बनाई गई रणनीति

रायपुर। विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री निवास में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई. विधायक दल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय सहित विधायक मौजूद रहे. बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई.

बैठक को लेकर तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि जबरदस्त बैठक हुई है. सभी विधायक गण शामिल हुए. मानसून सत्र को लेकर रणनीति तय की गई है. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. बलौदाबाजार हिंसा के मामले को लेकर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि घटना हुई है. सरकार जवाब देने के लिए तैयार है.

विधायक दल की बैठक को लेकर विधायक भावना वोरा ने कहा कि बैठक में सभी विधायकों से चर्चा की गई है. मानसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार की गई. कई विधायक नए हैं जो विधानसभा सत्र में पहली बार शामिल होंगे. विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है. विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर जो बयान दे रहा है उन्हें पहले अपने 5 साल के कार्यकाल को देखना चाहिए.

6 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में लोन ऑर्डर की स्थिति अच्छी हुई है पिछले 5 साल के मुकाबले अपराध के ग्राफ में कमी आई है.

विधानसभा घेराव की तैयारी के लिये पीसीसी अध्यक्ष बैज ने रायपुर, धमतरी में लिया बैठक

रायपुर। राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस ने 24 जुलाई को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। विधानसभा घेराव की तैयारियों के लिये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर और धमतरी जिला कांग्रेस की बैठक लिया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी पूरी ताकत के साथ विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को सफल बनायें।

कांग्रेसजनों को संबोधित करते हुये कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह विधानसभा घेराव राज्य के नागरिकों की रक्षा के लिये आवश्यक है। सरकार नागरिकों की सुरक्षा के प्रति उदासीन है। सरकार को मजबूर करेंगे की वह राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारे। भाजपा के राज में शांत छत्तीसगढ़ अशांत हो गया है। अराजकता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अपराधी इतने ज्यादा बेलगाम हो गये है कि राज्य में एसपी कलेक्टर कार्यालय जलाये जा रहे माबलीचिंग हो रही, थाने में चाकूबाजी हो रही सरकार सुशासन का राग अलाप रही। जबसे राज्य में भाजपा की सरकार बनी है। नागरिको को भय के माहौल जीवन जीना पड़ रहा है। अपराधी बेलगाम हो गये है। साय सरकार के राज में महिलाओं के प्रति अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गयी है। मासूम बच्चियों के साथ घृणित दुराचार की घटनाये बढ़ गयी। रोज समाचारों में प्रदेश भर में तीन से चार मासूम अबोध बच्चियों के साथ तथा सामूहिक दुराचार की घटनाओं की खबरे सामने आ रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 6 महीने की साय सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था खस्ताहाल में पहुंच गई है, 6 माह में ही राजधानी में गोलीबारी की 4 घटना हुई है। अंतर्राज्यीय गैंगस्टर राज्य मे पैर पसार रहे है सरकार है की मूकदर्शक बनी हुई है। 6 माह में राज्य में 300 से अधिक बलात्कार, 80 सामूहिक बलात्कार, 200 से अधिक हत्यायें।

तीन आईपीएस और 4 आईएएस का तबादला

रायपुर। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज जारी आदेश के मुताबिक श्याम लाल धावड़े, भा.प्र.से.(2008), आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है। श्याम लाल धावडे, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

डोमन सिंह, भा.प्र.से. (2009), अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर तथा अतिरिक्त प्रभार अपर आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पदस्थ करता है।

विनीत नंदनवार, भा.प्र.से. (2013), प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है। अभिषेक अग्रवाल, रा.प्र.से. (2013), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है।

2 आईपीएस समेत 3 अधिकारियों की बदली

राज्य सरकार ने 19 जुलाई को दो आईपीएस समेत तीन अधिकारियों का तबादला किया है। जारी लिस्ट में दो आईपीएस अफसर और एक राज्य पुलिस सेवा अधिकारी का नाम शामिल है। सरकार ने बलरामपुर रामानुजगंज के एसपी लाल उमेद सिंह को बदल दिया है। उन्हें मुख्यमंत्री सुरक्षा का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं वर्तमान पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रफुल्ल ठाकुर को चौथी बटालियन भेजा गया है। लाल उमेद सिंह की जगह पर राजेश अग्रवाल अब बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक होंगे।

मुख्यमंत्री ने 1 हजार करोड़ रु. अनुदान देकर बिजली बिल में 13 प्रतिशत की वृद्धि रुकवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा जो 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है उसकी सराहना करते हुए प्रदेश के अनेक उपभोक्ता संरक्षण, औद्योगिक तथा महिला संगठनों ने श्री साय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया है। मुख्यमंत्री श्री साय को प्रेषित पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष श्री मोहन एंटी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 1 जून 2024 को प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जो बिजली की नई दरें घोषित की गई है उसमें आपके द्वारा दी गई राहत की बहुत ही विशेष भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि विरासत में नई सरकार को 4 हजार 420 करोड़ रुपए का घाटा तोहफे के रूप में मिला था, यदि उस आधार पर नई बिजली दरें घोषित की जाती तो लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित थी। पत्र में कहा गया है, यह हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश में आपके जैसा सरल, सौम्य, संवेदनशील लेकिन अपने निर्णयों में सुदृढ़ मुख्यमंत्री मिला है। जो 21 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित थी वह आपकी संवेदनशीलता की वजह से ही सभी श्रेणियों में औसतन 8.35 प्रतिशत पर आकर थम गई। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तो आपका निर्णय वरदान ही साबित हुआ है। आपने एक ओर जहां हॉफ बिजली बिल योजना को जारी रखते हुए अपने वार्षिक बजट में इसका प्रावधान कर दिया है वहीं दूसरी ओर घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में मात्र 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है जो कि नगण्य है तथा एफोर्डेबल है। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए आपने राज्य शासन की ओर से 1000 करोड़ रुपए का जो अनुदान स्वीकृत किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम होगी।

यह राहत वास्तव में प्रदेश की गरीब एवं मध्यम वर्गीय जनता के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संबल साबित होगी।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

जनता अब साय नही,असहाय सरकार कह रही

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि साय सरकार में महंगी बिजली और लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है अब भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं लेकिन उनकी सरकार ही उनके बातों को अनसुना कर रही है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल विधायक, राजेश मूणत, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी प्रदेश में बिगड़ती क़ानून व्यवस्था, महंगी बिजली, अनियमित जीएसटी को लेकर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। आखिर यह सरकार किसके हाथों की कठपुतली बनकर बैठी है? किसके इशारे पर नाच रही है? 7 महीना में ही साय सरकार अलोकप्रिय हो गई है चारों तरफ अराजकता फैल चुका है जंगलराज कायम हो गया है हर वर्ग हताश और परेशान है, डरा सहमा हुआ है। जब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की कोई सुनवाई नही है फिर प्रदेश के पौने तीन करोड़ जनता की समस्याओं का सुध लेगा कौन? प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 7 महीने में जितने भी फैसले किए हैं सारे फैसले जन विरोधी रहा है बिजली दर में वृद्धि से प्रदेश के 44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के साथ किसान और उद्योगपति, व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं।

भूमि आबंटन संबंधी मंत्रिमंडल का निर्णय जनहित के खिलाफ

रायपुर। साय मंत्रिमंडल द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा जनहित में लिये गये भूमि संबंधी निर्णय को निरस्त करने की प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कड़ी निंदा किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने आम जनता के हित में तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि का सरकार को प्रतिफल वसूलने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने के लिये पारदर्शी नियम बनाया था। इस नियम से भूमि के आबंटन की पुरानी पद्धति में बदलाव हुआ था तथा भूमि आबंटन के लिये शासकीय गाइडलाइन से 150 प्रतिशत शुल्क निर्धारित किया गया था। भूमि आबंटन की प्रक्रिया पारदर्शी थी तथा सरकार के खजाने की भी वृद्धि हुई थी। वर्षों से शासकीय भूमि में काबिज लोगों को उसके मकानों, दुकानों आदि का मालिकाना हक मिला था। इस निर्णय को निरस्त किया जाना गलत है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार किसी भी दल की वह जब कोई निर्णय लेती है तो संविधान प्रदत्त शक्तियों के द्वारा लेती है। सरकार बदलने के बाद पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा लिये गये फैसले को बदलना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

किसानों के साथ मजाक कर रही है सरकार: वर्मा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बे-मौसम बारिश, ओलावृष्टि और तूफान से किसानों की खेती और मकानों हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति और फसल बीमा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रभावितों के साथ भद्दा मजाक किया है। नुकसानी हजारों और लाखों में हुई है, लेकिन क्षतिपूर्ति के नाम पर किसी को कुछ नहीं मिला, जिन्हें मुआवजा देने का आश्वासन दिया जा रहा है वह रकम भी अपमानजनक है, पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि अंबिकापुर जिले के भैयाथान इलाके के दर्जनभर गावों में ओलावृष्टि और तूफान से किसानों की खेती पूरी तरह चौपट हो गई थी, घर-बार उजड़ गए थे, ऐसे ही एक प्रभावित किसान जिसके दो एकड़ में गेहूं की फसल चौपट होने के साथ ही घर टूट गया था, अब तक एक नया पैसा नहीं मिला, उससे कहा जा रहा है कि मकान और फसल के नुकसानी के एवज में उसे मुआवजे के तौर पर मात्र 1370 रुपया दिया जायेगा। इसी तरह केवल भैयाथान इलाके के 455 किसानों की फसलें बर्बाद हुई, केवल इसी क्षेत्र में ही 172 घरों को नुकसान हुआ था.

मलेरिया और डायरिया से हो रही मौत यह सरकार की पोल खोल रही

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि 2024 में भी यदि लोग मलेरिया और डायरिया से मर रहे हैं यह डबल इंजन सरकार की पोल खोल रही है। मलेरिया, डायरिया से लगातार बढ़ती मौत का हाई कोर्ट संज्ञान लेकर राज्य सरकार को नोटिस देना प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। स्वास्थ्य विभाग के कार्य प्रणाली पर कितनी शर्म की बात है लगातार स्वास्थ्य मंत्री झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे सच के सामने झूठ का कद हमेशा छोटा ही रहता है इसीलिए हाई कोर्ट संज्ञान लेकर शासन को नोटिस भेजा जाता है की इतनी बड़ी लापरवाही? प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि जून का महीना मलेरिया माह घोषित होने के बावजूद विष्णु देव साय के शासन की ओर से बचाव के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जाना और सिर्फ कागजों और मीडिया में झूठ बोलते रहना भाजपा शासन के लापरवाही के कारण प्रदेश में मलेरिया, डायरिया फिर से पैर पसार रहा है। पूर्ववर्ती 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ऐसे ही मलेरिया और डायरिया से लोगों की हजारों मौत होती रही। 2018 में जब भाजपा के 15 साल के कुशासन का अंत हुआ था और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय छत्तीसगढ़ में मलेरिया की संक्रमण दर 2.63 प्रतिशत था जो 5 साल के कांग्रेस के सुशासन में मलेरिया उन्मूलन अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के फलस्वरुप घटकर मात्र 0.99 प्रतिशत रह गई थी।

मोवा बाजार चौक रायपुर का नामकरण शहीद भरत लाल साहू चौक करने का निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने शहीद भरत लाल साहू की स्मृति को अक्षुण्ण रखते हुए मोवा बाजार चौक रायपुर का नामकरण उनके नाम से शहीद भरत लाल साहू चौक करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि एसटीएफ के आरक्षक भरत लाल साहू 17 जुलाई को बीजापुर जिले के मंडीमरका के जंगल में सर्चिंग के दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने की वजह से शहीद हो गए थे। शहीद भरत लाल साहू रायपुर के मोवा बाजार के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं मंत्रिपरिषद के सहयोगियों ने शहीद भरत लाल साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही उनकी स्मृति में मोवा बाजार चौक रायपुर का नामकरण शहीद भरत लाल साहू चौक किए जाने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन की बड़ी कार्रवाई

जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही पर 6 ईई निलंबित, 4 को नोटिस

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश के बाद आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने छह कार्यपालन अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। साथ ही चार जिलों के कार्यपालन अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंत्रालय से आज छह कार्यपालन अभियंताओं के निलंबन के आदेश और चार कार्यपालन अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने और त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग किए जाने को गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए जगदलपुर के कार्यपालन अभियंता जगदीश कुमार, बिलासपुर के कार्यपालन अभियंता यू.के. राठिया, बैकुंठपुर के कार्यपालन अभियंता चंद्रबदन सिंह, बेमेतरा के कार्यपालन अभियंता आर.के. धनंजय, अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता एस.पी. मंडावी और सुकमा के कार्यपालन अभियंता जे.एल. महला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं दुर्ग के कार्यपालन अभियंता उत्कर्ष पाण्डेय, बालोद के कार्यपालन अभियंता सुक्रांत साहू, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के कार्यपालन अभियंता एस.एस. पैकरा तथा सारंगढ़-बिलाईगढ़ के कार्यपालन अभियंता कमल कंवर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विगत दिनों जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान इसे राज्य और केंद्र सरकार की महत्वाकांयोजना बताते हुए अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक काम करने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए थे।

उन्होंने जल जीवन मिशन के प्रगतिरत कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने को कहा था। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी मिशन के कार्यों पर नाखुशी जाहिर करते हुए अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा गांवों में शत-प्रतिशत घरों में नल से पानी पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह और त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन द्वारा निलंबन के बाद कार्यपालन अभियंता जगदीश कुमार का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता कार्यालय कोंडागांव, यू.के. राठिया का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता कार्यालय रायपुर, चंद्रबदन सिंह का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता कार्यालय सरगुजा, आर.के. धनंजय का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता कार्यालय दुर्ग, एस.पी. मंडावी का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता कार्यालय बिलासपुर और जे.एल. महला का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता कार्यालय जगदलपुर नियत किया गया है। नियमानुसार निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई वाले चारों कार्यपालन अभियंताओं को सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में प्रतिवाद प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जाएगा कि संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। तदुपरांत शासन द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, दंपती और मासूम बच्चे की मौके पर मौत

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया. जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामलों दर्ज कर जांच में जुट गई है. मृतकों को शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है. यह घटना सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम मंगारी की है. जानकारी के अनुसार, नेशनल हाईवे 43 में तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक के चक्कर में बाइक पर सवार होकर जा रहे परिवार को चपेट में ले लिया. भीषण हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में दंपती और उनका 7 वर्षीय मासूम बेटा शामिल हैं. मृतक कहां के रहने वाले हैं इसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी है. पुलिस पुरे मामले की जांच मे जुट गई है.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.